वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ीर्र्ें एूर्र्ें) मंगलवार यानी 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश करने जा रही हैं। बजट से पहले वित्त मंत्री ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक: 80 दिनांक:23-07-2024 मंगलवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

'नेम-प्लेट' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा कि बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। जब-जब इस देश में संविधान का उल्लंघन करने की कोशिश की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अपनी भूमिका निभाता है।

इस साल जीडीपी 7 प्रतिशत रहने का अनुमान-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री ने वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वे किया पेश

नई दिल्ली(ईएमएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वे सोमवार को सदन में पेश किया। इस आर्थिक सर्वे में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश की वास्तविक जीडीपी या वृद्धि दर 6.5-7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर और निजी निवेश में निरंतर गति से पूंजी निर्माण वृद्धि को बढ़ावा मिला है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में 2023-24 में वास्तविक रूप से 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का राजकोषीय घाटा (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 1.6 प्रतिशत अंक बढ़ा।

आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने कहा है कि सेवा क्षेत्र एक प्रमुख रोजगार प्रदाता बना हुआ है वहीं निर्माण क्षेत्र भी हाल ही में प्रमुखता से बढ़ रहा है, जो बुनियादी ढांचे के लिए सरकार की ओर की गई पहल नतीजा है। सर्वे के अनुसार खराब ऋणों की विरासत के कारण पिछले एक दशक में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन कम हुआ पर 2021-22 की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को बहुप्रतीक्षित केंद्रीय बजट 2024-25 के अनावरण से ठीक पहले सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।

एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस

सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक, देश की प्रगति को और रफ्तार देने के लिए कृषि क्षेत्र इंजन का काम करेगा और सर्वे में एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसके अलावा सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण पर देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर रहा है। इसके साथ ही भारत को ड्रोन हब बनाने पर भी सरकार का फोकस रहेगा।

बेरोजगारी घटी अब रोजगार पर जोर

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में साल 2030 तक औसतन सालाना करीब 78.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है। हालांकि, इसमें साफ किया गया है कि देश में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है और कोविड-19 महामारी के बाद से इसमें गिरावट आ रही है। 15 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर 6.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 तक 6.7 प्रतिशत पर आ गई।

महिला स्वरोजगार में तेजी

इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि महिला सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट में तेजी आई है और सरकार के प्रयासों के चलते भारत की 57.3 प्रतिशत वर्कफोर्स सेल्फ-एम्प्लॉयड है और इसमें महिलाओं की भागीदारी उत्साह पैदा करने वाली है, जिसमें महिला सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट में जबर्दस्त बदलाव देखने को मिला है।

बैंकों की बैलेंस शीट दुरुस्त

इकोनॉमिक सर्वे में कंपनियों और बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत होने का दावा किया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के कर्मचारियों पर पडऩे वाले असर को लेकर काफी अनश्चितता है। सर्वे रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया है कि एआई से प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन इसका कुछ सेक्टर्स में रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

विदेशी भारतीयों ने जमकर भेजा पैसा

सर्वे में ये भी जिक्र किया गया है कि जो भारतीय मूल के लोग दुनिया के तमाम देशों में रह रहे हैं, उन्होंने अपने परिजनों को जो पैसा भेजा है, उसका आंकड़ा लगातार बढ़ा है। डेटा के मुताबिक, विदेश में बसे भारतीयों ने 2024 के दौरान देश में 124 अरब डॉलर का रेमिटेंस भेजे हैं। साल 2025 में इसके 129 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान।

भारतीय बाजार का प्रदर्शन शानदार

भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यस्थ है और आर्थिक सर्वे में इसकी ग्रोथ स्टोरी में कैपिटल मार्केट की अहम भूमिका रही है। स्टॉक मार्केट ग्लोबल टेंशन और तमाम आर्थिक झटकों के बीच शानदार परफॉर्मेंस दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, शेयर मार्केट का निफ्टी-50 इंडेक्स वित्त वर्ष 24 के दौरान 26.8 फीसदी की बढ़त में रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 8.2 फीसदी की गिरावट में था।

महंगाई में कमी की उम्मीद

इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में महंगाई दर में गिरावट आ सकती है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष में महंगाई दर के 4.5 फीसदी पर रहने का अनुमान जताया है।

कॉलेज पासआउट दो से में एक के पास रोजगार के लिए जरूरी योग्यता नहीं

आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या का 65 प्रतिशत 35 वर्ष से कम उम्र का है, लेकिन उनमें से कई लोगों के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है। अनुमान बताते हैं कि लगभग 51.25 प्रतिशत युवा रोजगार के योग्य माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि सीधे कॉलेज से बाहर आने वाले लगभग दो में से एक युवा अब भी आसानी से रोजगार के योग्य नहीं है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले दशक में स्किल्ड युवाओं का प्रतिशत लगभग 34 प्रतिशत से बढक़र 51.3 प्रतिशत हो गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने बताया कि भारत में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति पर एनएसएसओ, 2011-12 (68वें दौर) की रिपोर्ट के अनुसार, 15-59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में लगभग 2.2 प्रतिशत ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वहीं, 8.6 प्रतिशत ने गैर-औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना 78.5 लाख रोजगार सृजन की जरूरत

आर्थिक सर्वे के अनुसार देश में बढ़ते मानव संसाधन को काम मुहैया कराने के लिए गैर कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना 78.5 लाख रोजगार सृजन करने की जरूरत है। सर्वे में कहा गया है कि कामकाज की उम्र का हर व्यक्ति नौकरी ही नहीं करेगा। उनमें से कुछ स्वरोजगार भी करेंगे और कुछ लोग नियोक्ता भी बनेंगे। सर्वे में कहा गया है कि देश का आर्थिक विकास नौकरियों से ज्यादा लोगों को आजीविका मुहैया कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी स्तर के सरकारों और निजी क्षेत्र को भी इस में योगदान देना होगा। आर्थिक सर्वे के अनुसार कृषि क्षेत्र का श्रम बल जो 2023 में 45.8 प्रतिशत है वह 2047 तक धीरे-धीरे घटकर 25 प्रतिशत पर पहुंच सकता है। इसलिए 2030 तक हमें गैर कृषि क्षेत्र में सालाना करीब 78.5 लाख रोजगार मुहैया कराने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का फैसला रोका, कहा- दुकानदारों को नाम बताने के लिए मजबूर न करें

नई दिल्ली(ईएमएस)। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के सरकारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया है। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहि ष्कार किया जा रहा है। यह चिंताजनक है।

भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। होटल चलाने वालों को भोजन के प्रकार यानी वह शाकाहारी है या मांसाहारी की जानकारी देनी होगी। लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

ये दुकानदारों के लिए हैं आर्थिक मौत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्वैच्छिक है और ये अनिवार्य नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने केस इसको लागू किया है। इसको देखें वहां पुलिस की तरफ से चेतावनी दे गई कि अगर नहीं करते तो करवाई होगी। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई की बात की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये विक्रेताओं के लिए आर्थिक मौत की तरह है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई औपचारिक आदेश पास किया है, जिस पर वकील ने कहा कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसे लागू रही है। पुलिस कमिश्नर ऐसे निर्देश जारी कर रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हमें स्थिति को इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि यह जमीनी हकीकत से ज्यादा बढ़ जाए। इसके तीन आयाम हैं - सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता और - तीनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये बात जस्टिस एसवीएन भट्टी ने कही जब सिंघवी ने कि ये पहचान का बहिष्कार है, आर्थिक बहिष्कार है।

यूपी के बाद उज्जैन और उत्तराखंड में आदेश जारी हुए

पहले मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने निर्देश जारी किया था कि कांवड़ रूट पर पडऩे वाले सभी होटल-ढाबे और रेहड़ी संचालक मोटे-मोटे अक्षरों में अपना नाम और मोबाइल नंबर का बोर्ड लगाएंगे। जिससे ताकि कांवड़ियों को सामान खरीदते वक्त कोई कन्फ्यूजन न रहे। इसके बाद 19 जुलाई को यही आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया।

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरिद्वार पुलिस ने भी अपने यहां यही आदेश जारी कर दिए। वाराणसी में काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में भी 20 जुलाई को पुलिस ने सभी दुकानों पर पहचान लिखने के लिए कहा है। यूपी के बाद 20 जुलाई को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों का नाम और मोबाइल नंबर लिखना जरूरी कर दिया गया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर दुकान खोलते हैं। उज्जैन में नगर निगम यह आदेश एक साल पहले ही दे चुका था। हालांकि, इस पर अमल नहीं हो रहा था। उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा था कि इस बार सावन के महीने में आदेश पर सख्ती से अमल करवाएंगे।

संघ से हटा प्रतिबंध, मायावती ने कहा.....तल्खी दूर करने के लिए

लखनऊ (ईएमएस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष और पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देशहित से परे है।

मायावती ने मामले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाकर पोस्ट में कहा, कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केन्द्र का निर्णय देशहित से परे और राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय है ताकि सरकारी नीतियों व इनके (भाजपा सरकार) अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो।

मायावती ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान व कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित व जनकल्याण में कार्य करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे संघ की गतिविधियां राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। मायावती ने निर्णय को अनुचित बताकर तुरंत वापस लेने की मांग की है। इसके पहले रविवार को, कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई को जारी एक कार्यालय ज्ञापन साझा किया, जो आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी से संबंधित है। आदेश में कहा गया है, ''उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए।

आदेश की तस्वीर के साथ कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि फरवरी 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और संघ के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था।

डिप्टी सीएम ने मांगा सीएम योगी के विभाग से कर्मचारियों के आरक्षण का ब्यौरा

-यूपी में अंदरूनी खींचतान के बीच केशव प्रसाद मौर्य का पत्र बना चर्चा का विषय

लखनऊ,(ईएमएस)। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ के विभाग को पत्र लिखा है जिसमें नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आरक्षण का ब्यौरा मांगा है। इस पत्र में केशव मौर्य ने कहा है कि वह इस मुद्दे को विधान परिषद में भी उठा चुके हैं।

सीएम योगी के नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर केशव प्रसाद मौर्य ने आउटसोर्सिंग या संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। पत्र में डिप्टी सीएम मौर्य ने लिखा कि-मैंने 11 अगस्त 2023 में इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाया था और अधिकारियों से जानकारी मांगी थी। 16 अगस्त 2023 को उन्होंने पत्र लिखा था, लेकिन जानकारी नहीं मिलने से एक बार फिर पत्र लिखा और अधिकारियों को आदेशित किया था कि शासनादेश के मुताबिक समस्त विभागों को सूचीवार एकत्र करके, संकलित कर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

यूपी में बीजेपी सरकार और संगठन के बीच अंदरूनी खींचतान के बीच डिप्टी सीएम मौर्य का यह पत्र चर्चा में आ गया। हाल ही में संगठन और सरकार के बीच मतभेद सामने आए थे। उसके बाद केशव मौर्य को दिल्ली बुलाया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की थी। इस बैठक में संगठन और सरकार के बीच तनाव को कम करने पर चर्चा हुई थी। नड्डा ने कहा था कि ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचे।

यूपी कार्यसमिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि जो आपका दर्द है, वही मेरा भी दर्द है और बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था और रहेगा। केशव मौर्य ने आगे कहा था कि 7 कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुला है। डिप्टी सीएम के बस बयान के बाद यूपी की सियासत चर्चा के केंद्र में आ गई थी जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गरम हो गया था। विपक्ष ने भी इस खींचतान पर तंज कसे थे।

खालिस्तानियों ने दी संसद भवन और लाल किला उड़ाने की धमकी

-सांसद वी शिवदासन को आया फोन, राज्यसभ4ा के सभापति को लिखा पत्र

नई दिल्ली,(ईएमएस)। केरल से राज्यसभा सांसद वी शिवदासन को धमकी भरा फोन आया है। सांसद के मुताबिक उन्हें फोन पर धमकी दी गई कि संसद भवन और लाल किले को बम से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह धमकी भरा फोन कॉल खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस (एसजेएफ) के नाम किया गया था। इस बात को लेकर सांसद वी शिवदासन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि उन्हें एसजेएफ के नाम पर फोन कॉल आया था। वी शिवदासन केरल से सीपीआई (एम) के सांसद हैं। धमकी देने वाले ने गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम लिया है।

राज्यसभा सभापति को पत्र में सांसद वी शिवदासन ने लिखा है कि मुझे सिख फॉर जस्टिस (एसजेएफ) के नाम पर एक धमकी भरा फोन आया था। उन्होंने लिखा है कि यह धमकी 21 जुलाई को रात 11 बजकर 30 मिनट पर मिली। सांसद ने बताया कि जिस वक्त उनके पास फोन आया वह आईजीआई एयरपोर्ट लाउंस में थे और उनके साथ सांसद ए रहीम थी मौजूद

नीट के विवादित सवाल की जांच के आदेश...उधर, संसद में हंगामा

लोकसभा में नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच बहस, कांग्रेस नेता बोले

देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड

नई दिल्ली(ईएमएस)। नीट मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम में फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले सवाल नंबर 19 की पड़ताल का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस माक्र्स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। इस पर आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लें। कोर्ट ने आदेश दिया कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर 2 जवाबों वाले सवाल की जांच के लिए एक 3 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बनाएं। एक्सपर्ट टीम उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर मंगलवारको 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजें। उधर, संसद के मानसून के पहले दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री बोले कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था, जो पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा- सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का यह कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, बेहद निंदनीय है।

प्रधान ने कहा कि 2010 में मनमोहन सिंह सरकार में कपिल सिब्बल शिक्षा सुधार के लिए 3 बिल लाए। उनमें से एक अनियमितता रोकने के लिए था। उसे किसके दबाव में वापस लिया गया। क्या यह निजी मेडिकल कॉलेजों के दबाव के कारण था? और वे (राहुल गांधी) हमसे सवाल पूछ रहे हैं।

संसद के मानूसन सत्र में नीट पेपर लीक मुद्द को लेकर चल रहे हंगामे के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पेपर लीक में नए रिकॉर्ड बना रही है। इसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी अखिलेश यादव के कार्यकाल में यूपी में हुए पेपर लीक की सूची है। संसद में अखिलेश यादव ने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में छात्र विरोध कर रहे हैं। जांच में खुलासे हो रहे हैं। लगातार गिरफ्तारियां की जा रहीं हैं। मेरा कहना है कि अगर यही शिक्षा मंत्री रहे तो छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। इसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम सार्वजनिक किया गया है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास सूची है कि अखिलेश यादव की सरकार में यूपी में कितने पेपर लीक हुए? उन्होंने कहा कि एनटीए ने 240 से ज्यादा परीक्षाएं कराईं। इनमें पांच करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश के लिए एकल परीक्षा कराने के लिए कहा था। पहले नीट परीक्षा सीबीएसई कराता था। अब यह नीट कराता है।

कांग्रेस सांसद बी मणिकम टैगोर ने कहा कि सात साल में 17 बार पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि 24 लाख परीक्षार्थियों की जिम्मेदारी सरकार ले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सात बार पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है। केंद्र सरकार कुछ भी नहीं छिपा रही है। एक और सांसद प्रेमचंदन ने कहा कि नीट भ्रष्टाचार परीक्षा के लिए शुरू हुए पंजीकरण से ही चालू हो गया था। उन्होंने मामले की जांच के लिए संसदीय जांच समिति बनाने की मांग की।

लगातार सातवां बजट पेश कर इतिहास रचेंगी निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली (ईएमएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं। इस तरह वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। हालांकि, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी देसाई के पास ही है। सीतारमण अगले महीने 65 वर्ष की हो जाएंगी। उन्हें 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था। इसी साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। तब से सीतारमण ने इस साल फरवरी में एक अंतरिम सहित लगातार छह बजट पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025) का पूर्ण बजट उनका लगातार सातवां बजट होगा। वह देसाई के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगी, जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच लगातार पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने से जुड़े कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट 26 नवंबर, 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर कुल 10 बजट पेश किए हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने नौ मौकों पर बजट पेश किया। प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आठ बजट पेश किए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 से 1995 के बीच लगातार पांच बार बजट पेश किया, जब वह पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे।

सुप्रीम कोर्ट में शंभू बार्डर खोलने के मामले की सुनवाई टली

नई दिल्ली (ईएमएस)। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बार्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नीट मामले में व्यस्त होने के कारण सोमवार को सुनवाई टल गई.

हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है. सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है.

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, कोर्ट इस पर तैयार हो गया था. जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा था कि वो इस मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई करेंगे.

तीन नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ दिल्ली कूच करेंगे किसान,15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च

नई दिल्ली (ईएमएस)। तीन नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ किसान अब दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में हैं। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इसका ऐलान किया गया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों की ओर से देशभर में ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की गई है। किसानों से संघु और शंभु समेत दिल्ली के लगते बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की गई है। फैसला लिया गया है कि ट्रैक्टर मार्च के साथ ही नए क्रिमिनल कानूनों की कॉपी को भी जलाया जाएगा।

किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 1 अगस्त को वह मोदी सरकार की अर्थी जलाएंगे। इस दौरान एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया है। किसानों ने रणनीति बनाई है कि 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। इस दौरान नए क्रिमिनल लॉ की कॉपी भी जलाई जाएगी। देशभर के किसानों से सरकार की नीतियों का विरोध करने की अपील की गई है। शंभू बॉर्डर पर किसान महीनों का राशन लेकर पहुंचने लगे हैं।

31 अगस्त तक किसानों से शंभु बॉर्डर पहुंचने की अपील

किसान लंबे समय से शंभु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 31 अगस्त को इस धरने को 200 दिन पूरे हो जाएंगे। किसान संगठनों ने इस दिन सभी किसानों से अपील की है कि वो बॉर्डर पर पहुंचे।वहीं, हरियाणा में 15 सितंबर को जिंद में और 22 सितंबर को हरियाणा के ही पीपली में किसानों की रैली आयोजित होने वाली है।किसानों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बेल देने की भी निंदा की। आशीष पर लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है।किसानों ने कहा कि बॉर्डर खुलते ही ट्रैक्टर में सामान भरकर हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे।

लोकसभा में सरकार ने 2012 की रिपोर्ट का हवाला देकर खारिज की मांग ,बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा

पटना (ईएमएस)। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नीतीश सरकार को केंद्र से करारा झटका लगा है। केंद्र ने साफ किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्र की तरफ से सोमवार को संसद में जवाब दिया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि विशेष राज्य का दर्जे के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। इसके तहत पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।

बिहार की मांग के बाद केंद्र की यूपीए सरकार ने 2012 में इसके अध्ययन के लिए मंत्रियों के ग्रुप का भी गठन किया था। इसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद के क्राइटेरिया के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। इसी को आधार बनाकर केंद्र ने एक बार फिर से बिहार सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि बीते कुछ सालों से बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की मांग लगातार उठती रही है। बिहार में एक बार फिर यह मांग जोर पकड़ रही है।

दूसरे राज्यों से भी उठ रही मांग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के मुताबिक, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रावधान है। इस समय देश में कुल 29 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश हैं। इनमें से 11 राज्य ऐसे हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। वहीं, अब भी बिहार, आंध्रप्रदेश, ओडिशा समेत पांच राज्य ऐसे हैं जो स्पेशल स्टेट का दर्जा दिए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पांच पैमाने तय किए गए हैं। इनमें राज्य में पहाड़ी इलाके और दुर्गम क्षेत्र ज्यादा हों। कम आबादी वाले राज्य या जनजातीय समुदाय का ज्यादा होना। इंटरनेशनल बार्डर वाले राज्य, इसकी सरहदें पड़ोसी देशों से लगती हों। आर्थिक और आधारभूत संरचना में पिछड़े राज्य। राज्य के पास इनकम का बड़ा स्रोत ना होना।

मानसून सत्र से पहले बोले पीएम मोदी ,जितनी लड़ाई लडऩी थी, लड़ ली; अब सिर्फ देश के लिए काम करें

नई दिल्ली (ईएमएस)। संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। मैं सावन के पहले सोमवार पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आज पूरे देश की नजर इस पर

जन हितैषी

नए विवाद को जन्म देगा केंद्र का आदेश

शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघ के कार्यक्रमों में हो सकेंगे शामिल

9 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों के सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। यह आदेश भारत सरकार के पर्सनल एवं पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन एवं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश पर डिप्टी सेक्रेटरी के हस्ताक्षर हैं। इस आदेश पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य शामिल होने की बात सामने आई थी। तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था। ऐसा ही प्रतिबंध 1966 में भी लगाया गया था। 1970 और अक्टूबर 1980 में भी केंद्र सरकार ने संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था। जब बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराया गया था। उस समय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अन्य पांच संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर प्रतिबंध लगाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के कार्यकाल में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं और संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध था। 58 साल से यह प्रतिबंध लगा हुआ था। इस प्रतिबंध को मोदी सरकार ने 9 जुलाई 2024 को हटा लिया है। इस आदेश के बाद अब कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी संघ के किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। अब कोई रोक-टोक नहीं होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक वैचारिक संगठन है। विचारधारा के प्रचार प्रसार को लेकर वह अपनी सोच के अनुसार विचारधारा को बढ़ावा देने का काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 80 से ज्यादा अनुवांशिक संगठन हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी संविधान के अनुसार नियम और कानून के तहत काम करते हैं। जहां विचारधारा के स्थान पर, मानवीय और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण का काम सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को करना होता है। हाल ही में जिस तरह से कई न्यायपालिका के जजों और बड़े-बड़े अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए सार्वजनिक रूप से इज़हार किया है। वह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में विचारधारा से संचालित होने वाले अन्य धार्मिक संगठन भी इसी तरह की मांग कर सकते हैं। जो भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत होगी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रमों में जाने की छूट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मिल गई है। अन्य धर्मों अथवा विचारधारा से संचालित इस तरह के संगठन, वह भी केंद्र सरकार से इसी तरह की छूट मांग सकते हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की क्या भूमिका होगी। इसे समझना भी बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुवांशिक संगठनों द्वारा किस तरह से नाथूराम गोडसे को अपना आराध्य माना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साहित्य में गांधी जी की भूमिका तथा भारतीय संविधान के बारे में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, वह संवैधानिक प्रावधान के विपरीत हैं। गांधी जी की हत्या को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुवांशिक संगठन समय-समय पर सही ठहराने का प्रयास करते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय संविधान के विपरीत एक अलग विचारधारा का पोषण करता है। ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को उसमें शामिल होने देने से, भविष्य में कई तरह की परेशानियां और विवादों का सामना केंद्र एवं राज्य सरकारों को करना पड़ सकता है। पिछले 58 सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों और शाखाओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। उसके बाद भी व्यक्तिगत तौर पर निजी आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकारी अधिकारी और कर्मचारी समय-समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। उस पर इसलिए कोई विवाद नहीं उठा, वह निजी हैसियत से कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उसके अनुसार कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुवांशिक संगठनों के कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से अधिकार पूर्वक शामिल हो सकेगा। इस आदेश पर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की तीव्र प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार के इस आदेश ने एक नए विवाद को जन्म दिया है। इस आदेश की जानकारी लगते ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर जाहिर कर दी है। महात्मा गांधी की हत्या के लिए कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार मानती है। न्यायालय से भले सबूत और तकनीकी के अभाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को न्यायालय द्वारा निर्दोष बताया गया। नाथूराम गोडसे को आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुवांशिक संगठन गांधी जी की हत्या को सही कदम बताते हैं। संघ के इतिहास में आज भी नाथूराम गोडसे को शहीद का दर्जा है। भारत ने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। महात्मा गांधी की हत्या के 75 वर्ष बाद और पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से भारत में गोडसेवाद एक बार फिर लौट कर सामने आया है, उसके बाद चिंता होना स्वाभाविक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद डेढ़ दशक तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सारी गतिविधियां बंद थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगातार प्रयास करने और महात्मा गांधी की हत्या में संघ की कोई भूमिका नहीं होने तथा 1962 के चीन भारत युद्ध के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रीयता के आधार पर प्रतिबंध समाप्त कराया था। एक बार फिर सामाजिक गतिविधियों में संघ सक्रिय हुआ था। 2014 के बाद से जिस तरह से गोडसे को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। नाथूराम गोडसे की मूर्तियां और मंदिर तैयार किये जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था तैयार की जा रही है। पिछले वर्षों में शासकीय अधिकारियों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी निष्ठा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जोड़ी है। उसके बाद इस आदेश पर तीव्र प्रतिक्रिया होना तय है। जिस तरह के हालात देश में बने हुए हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर देश में विभिन्न समुदायों को आपस में बांटा जा रहा है। ऐसे समय पर भारत सरकार द्वारा संघ के कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों के शामिल होने की छूट देने से, सरकार ने एक नये विवाद को जन्म दिया है। इस आदेश पर तीव्र प्रक्रिया होना तय है।

देश में बढ़ रही कुतर्क की राजनीति

राजनीति में सकारात्मक दिशा के अभाव में देश को जो नुकसान उठाना पड़ता है, वह भले ही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं दे, लेकिन उससे समाज पर प्रभाव अवश्य ही होता है। अगर यह प्रभाव नकारात्मक चिंतन की धारा के प्रवाह को गति देने वाला होगा तो देश को भी अपने अस्तित्व के लिए जूझना पड़ता है। वर्तमान में जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, उसे भटकाव पैदा करने वाली राजनीति कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इतना ही नहीं, जो विषय राजनीति के नहीं होने चाहिए, उनको भी राजनीतिक दल राजनीति के दल दल में ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के किसी भी निर्णय का अपने हिसाब से परिभाषित करना राजनीति का प्रिय विषय बनता जा रहा है। इससे प्राय: मूल विषय बहुत पीछे छूट जाता है और बहस कहीं और चली जाती है।

आज के राजनीतिक वातावरण का अध्ययन किया जाए तो यही परिलक्षित होता है कि सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने एजेंडे हैं। कोई भी किसी दूसरे की बात को ऐसे तर्क देकर उसका प्रक्षालन करते हैं, जैसे केवल उनकी ही बात सही है और बाकी सब गलत बयानी कर रहे हैं। हालांकि यह बात सही है कि कमी सभी जगह होती है, लेकिन कुछ अच्छे काम भी होते हैं, आज इन अच्छे कामों की चर्चा कहीं भी नहीं हो रही है। सब एक दूसरे की गलतियां निकालने में ही राजनीति का मुख्य उद्देश्य बनता जा रहा है। यह राजनीति की सकारात्मक दिशा तो कतई नहीं मानी जा सकती। प्रछख्ठ इसे नकारात्मक राजनीति अवश्य कहा जा सकता है। ऐसी राजनीति आम जनता में भटकाव पैदा करती है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि जो जनता सरकार के विरोध का विचार रखती है, वह विपक्ष की हर बात को सही मानकर ही व्यवहार करेगी और जो विपक्ष की बातों पर भरोसा नहीं करती, उसे सत्ता पक्ष की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वास्तव में ऐसी राजनीति के बजाय देश हित की राजनीति करने की ओर सभी दलों को आगे आना चाहिए। लेकिन आज के वातावरण में ऐसा होना संभव नहीं लगता। क्या यह सही नहीं है कि देश में भाजपा के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, लेकिन विपक्ष इस बहुमत वाली सरकार को पराजित सरकार कहकर लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है। हालांकि यह मानने में कोई अतिरेक नहीं है कि विपक्ष पहले से मजबूत हुआ है, लेकिन वह विपक्ष में ही है। इसको भी खुले मन से स्वीकार करने की मानसिकता बनानी होगी, तभी हम कह सकते हैं कि राजनीति देश को सही दिशा में ले जाने की हो रही है।

आजकल समाचार के विभिन्न माध्यमों पर सामयिक विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन इन चर्चाओं में सभी तरफ से पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्तियों को ही शामिल करने का चलन हो गया है। दूसरे की बात को नकारना ही इन चर्चाओं का एकमेव सिद्धांत बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, कोई एंकर अपनी ओर से भारत के चिंतन पर आधारित कोई तथ्य रखता है तो उस एंकर को भी किसी राजनीतिक दल का समर्थक बताने में कोताही नहीं की जाती। हो सकता है कि कोई पत्रकार विचारधारा से किसी राजनीतिक दल की बात को सही ठहराने की वकालत कर रहा हो। क्योंकि आज के समय में अधिकांश पत्रकार और समाचार पत्र किसी न किसी राजनीतिक दल का खुल कर समर्थन करता है तो कोई विरोध की शैली ही अपनाता है। ऐसी पत्रकारिता भी ठीक नहीं कही जा सकती, लेकिन कई समाचार चैनल ऐसे भी हैं जो निष्पक्ष तरीके से बहस कराते हैं। यह एंकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही सवाल करते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की ओर से एंकर को सवालों के घेरे में खड़े करना ठीक नहीं कहा जा सकता। आजकल जो डिबेट चल रही हैं, उनमें विपक्ष की ओर से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे उन्होंने भाजपा को हरा दिया है। इसके लिए अगर कोई एंकर विजयी सांसदों की संख्या बताता है तो तर्क वितर्क प्रारंभ हो जाता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ज़ब यह तर्क वितर्क से आगे बढ़कर कुतर्क की शैली में आ जाता है तो विवाद होने लगता है। राजनेताओं को राजनीतिक लड़ाई केवल दलीय आधार पर करना चाहिए, लेकिन यहां पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने तरकस से तीर निकालने का प्रयास किया जाता है। अगर भाजपा का कोई प्रवक्ता तीसरी बार सरकार बनाने की बात को लोकतंत्र की विजय निरुपित करता है तो इसमें गलत क्या है। इसे विपक्ष को खुले मन से स्वीकार करने में हिचक क्यों हो रही है। एक कहावत है कि सच बहुत कड़वा होता है, जिसने सच को स्वीकार करना सीख लिया, वह कुतर्क करने की चेष्टा नहीं कर सकता।

लोकतंत्र क्या है? इसकी परिभाषा या तो राजनेता जानते नहीं हैं या फिर जानते हुए भी नहीं जानने का नाटक करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र की परिभाषा ''जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। राजनेता तो मात्र जनता के प्रतिनिधि ही हैं। लेकिन वर्तमान में राजनेता जनता से ऊपर मानने की ओर प्रवृत हो चुके हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारत की जनता ने लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा सीट भाजपा को दी हैं। इसे सीधे अर्थों में प्रदर्शित किया जाए तो यही कहना उचित होगा कि भाजपा ही जनता की पहली पसंद है। उसे जनता ने 240 सीट दी है। बाकी का कोई भी दल तीन अंकों की संख्या तक भी नहीं पहुँच सका है। ऐसे में क्या यह नहीं कहा जाना चाहिए कि मिलकर चुनाव लड़ने के बाद भी विपक्ष सरकार बनाने में सफल नहीं हो सका। इसे हार ही कहा जाएगा, लेकिन विपक्ष इसी हार को ऐसे प्रचारित कर रहा है, जैसे यह उसकी बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस ने भले ही अपनी स्थिति में सुधार करते हुए प्रदर्शन किया हो, लेकिन इसे बड़ी जीत नहीं कहा जा सकता। सत्य यह भी है कि कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है, वह उसके अपने परिश्रम का परिणाम नहीं है। उत्तरप्रदेश में अगर सपा का समर्थन नहीं होता तो कांग्रेस किस स्थिति में होती, यह अनुमान लगाया जा सकता है। यहां एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है, कांग्रेस राष्ट्रीय दल होने के बाद भी सपा से बहुत पीछे है। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यही लोकतंत्र की जीत है। तर्क वितर्क और कुतर्क करने की राजनीति से भ्रम की स्थिति बनती है। इस प्रकार की राजनीति का कोई ठोस आधार नहीं होता। (लेखक- सुरेश हिंदुस्तानी/ईएमएस)

फिर आतंकी हमलें, सैनिकों का बलिदान व्यर्थ न जाये

लगातार जम्मू-कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाएं चिन्ता का कारण बन रही है। डोडा जिले में एक आतंकी हमले में कैप्टन समेत सेना के चार जवानों और जम्मू कश्मीर के एक पुलिसकर्मी का बलिदान अब यही दर्शा रहा है कि शांति एवं अमन की ओर लौटा जम्मू-कश्मीर एक बार फिर आतंकवादी आघातकारी घटनाओं की भेंट चढ़ रहा है, इन घटनाओं का माकुल जबाव नहीं दिया गया तो यह घाटी एक बार फिर खूनी घाटी बन जायेगी। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कठुआ में एक सैन्य अफसर सहित पांच जवान आतंकियों का निशाना बन गए थे। इसके पहले भी जम्मू संभाग में ही सेना के कई जवान आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। ये बहुत चिंतित करने वाले त्रासद एवं घिनौने घटनाक्रम हैं कि पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी के साथ-साथ जम्मू संभाग में भी आतंकियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हाल की कुछ घटनाओं से तो यह भी लगता है कि आतंकियों ने जम्मू संभाग को अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना लिया है। एक ऐसे समय जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी हो रही है, तब आतंकियों का सक्रिय होना और सफलतापूर्वक अपने मनसूबों को कामयाब करना गंभीर चिंता का विषय है।

ज्यादा चिन्ताजनक यह है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी न केवल घुसपैठ कर रहे हैं, बल्कि अपनी गतिविधियों को अंजाम देने और इस क्रम में सेना को निशाना बनाने में भी सफल हो रहे हैं। सरकार को उन खूनी हाथों को खोजना होगा अन्यथा खूनी हाथों में फिर खुजली आने लगेगी। हमें इस काम में पूरी शक्ति और कौशल लगाना होगा। आदमखोरों की मांद तक जाना होगा। अन्यथा हमारी खोजी एजेंसियों एवं सेना की काबिलीयत पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा कि कोई दो-चार व्यक्ति कभी भी पूरे प्रांत की शांति और जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर सकते हैं, हमारी संवेदनाओं को झकझोर सकते हैं। संवेदनाओं एवं भावनाओं को झकझोर भी रहे हैं, जब आतंकवादी हमलों में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे घर की डयोढ़ी पर आते हैं तब कारुणिक माहौल को देखकर दिल दहल उठता है क्योंकि देश के लिए अपना सर्वोच्च लुटा देने वाला जवान किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का पिता होता है। हर आंख में आंसू होते हैं। किसी की गोद, किसी की मांग सूनी हो जाती है। देशवासी सोचने को विवश हैं कि वे शोक संत्पत परिवार के साथ करुणा और पीड़ा को कैसे बांटें।

डोडा वारदात की जिम्मेदारी लेने वाले 'कश्मीर टाइगर्स' जैसे आतंकी संगठनों की ताजा बौखलाहट की एक बड़ी वजह जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली को लेकर बढ़ी सरगर्मी है। राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए अगले चंद महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में, आतंकियों की बेचैनी समझी जा सकती है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में घाटी में लोग मतदान केंद्रों पर उमड़ पड़े और दशकों पुराना रिकॉर्ड टूटा, अगर विधानसभा चुनाव में लोगों का उत्साह और बढ़ा, तो जिन 'स्लीपर सेल्स' की बदौलत वे दहशत का अपना पूरा कारोबार चलाते हैं, वे भी मुख्यधारा के प्रति आकर्षित होकर, उनके खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने घाटी के बजाय जम्मू संभाग में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया जा सके और सीमा पार के आकाओं से मदद हासिल करने का सिलसिला जारी रहे।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान से पाकिस्तान बौखलाया है। इसी का परिणाम है लगातार हो रहे आतंकी हमलें। इन हमलों ने आंतरिक सुरक्षा के लिये नये सिरे से चुनौती पैदा की है। जम्मू में रियासी, कठुआ और डोडा के आतंकी हमले चिन्ता का बड़ा कारण बने है। जम्मू-कश्मीर का माहौल सुधरने के बाद वहां के बाजार, पर्यटक स्थल गुलजार हुए हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। इसलिए देशद्रोही नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति आए और वहां पर निर्वाचित सरकार काम करे। केन्द्र में गठबंधन वाली मोदी सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती है। क्या इन आतंकी घटनाओं को केन्द्र सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है? जो सरकार पाकिस्तान में घूस कर बदला ले सकती है, वह सरकार अब तक शांत क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। आतंकी जिस तरह अपनी रणनीति बदलकर सुरक्षा बलों को कहीं अधिक क्षति पहुंचाने में समर्थ दिखने लगे हैं, वह किसी बड़ी साजिश का संकेत है। एक ओर सीमा पार से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण करना होगा, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को नए सिरे से सबक भी सिखाना होगा। यह इसलिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में आतंकी हमलों में बलिदान होने वाले सैनिकों की संख्या कहीं अधिक बढ़ी है।

पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठानों की मदद से यह आतंक का खेल फिर शुरू कर रहा है। कहीं न कहीं दिल्ली में बनी गठबंधन सरकार को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पाक पोषित आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में शांति एवं अमन को कायम नहीं रहने देंगे। एक आंकड़े के अनुसार पिछले तीन वर्ष में करीब 50 जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा है। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। आतंक को करारा जवाब केवल तभी नहीं दिया जाना चाहिए, जब एक साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को बलिदान देना पड़े। वास्तव में हमारे एक भी सैनिक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। डोडा की घटना के बाद यह जो कहा जा रहा है कि सैनिकों के बलिदान का बदला लिया जाएगा, उसे न केवल पूरा करके दिखाया जाना चाहिए, बल्कि आतंकियों, उनके आकाओं और उन्हें सहयोग-समर्थन देने वालों पर ऐसा करारा प्रहार किया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी हरकतों से हमेशा के लिए बाज आएं। पाकिस्तान भले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा हो, लेकिन वह जम्मू कश्मीर में पहले की तरह ही आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। उसकी घरेलू व विदेश नीति 'कश्मीर' पर ही आधारित है। चूंकि इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन उसे उकसाने में लगा हुआ होगा, इसलिए भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा।

केन्द्र सरकार ने कश्मीर में विकास कार्यों को तीव्रता से साकार किया है, न केवल विकास की बहुआयामी योजनाएं वहां चल रही है, बल्कि पिछले 10 सालों में कश्मीर में आतंकमुक्त करने में भी बड़ी सफलता मिली है। बीते साढ़े तीन दशक के दौरान कश्मीर का लोकतंत्र कुछ तथाकथित नेताओं का बंधुआ बनकर गया था, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये जो कश्मीर देश के माथे का ऐसा मुकुट था, जिसे सभी प्यार करते थे, उसे डर, हिंसा, आतंक एवं दहशत का मैदान बना दिया। लेकिन वहां विकास एवं शांति स्थापना का ही परिणाम रहा कि चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेकर लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया। बढ़ती आतंकी घटनाओं पर गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर बनाए हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुरक्षा बल आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देगा लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा बलों को आतंकियों के प्रति अपनी रणनीति बदलनी होगी और आतंकी जिन बिलों में छिपे होंगे उन्हें वहां से निकालकर ढेर करना होगा। आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी करनी होगी और साथ ही आतंकियों के मददगारों की भी पहचान करनी होगी, तभी आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया जा सकता है।

पुलिस के आला अधिकारी यदि यह कह रहे हैं कि घाटी के नागरिक समाज में पाकिस्तानी 'घुसपैठ' को बढ़ावा देने में कतिपय राजनीतिक दलों का रुख भी जिम्मेदार रहा है, तो क्या यह आधारहीन है? इसका मुकाबला हर स्तर पर हम एक होकर और सजग रहकर ही कर सकते हैं। यह भी तय है कि बिना किसी की गद्दारी के ऐसा संभव नहीं होता है। ताजा आतंकी हमलों के विकराल रूप कई संकेत दे रहे हैं, उसको समझना है। कई सवाल ख़ड़े कर रहा है, जिसका उत्तर देना है। यह पाकिस्तान का बड़ा षड़यंत्र है इसलिए इसका फैलाव भी बड़ा हो सकता है। ये घटनाएं चिल्ला-चिल्ला कर कह रही हैं हमारी खोजी एजेन्सियों से, हमारी सुरक्षा व्यवस्था से कि वक्त आ गया है अब जिम्मेदारी से, सख्ती से और ईमानदारी से जम्मू-कश्मीर को संभालें। (लेखक- ललित गर्ग / ईएमएस)

अच्छे वैज्ञानिक अनुसन्धान हेतु वैज्ञानिकों पर भरोसा आवश्यक

विज्ञान पर तो दुनिया विश्वास करती है एक हालिया अध्ययन के अनुसार दुनिया भर के लोगों ने वैज्ञानिकों पर भरोसा व्यक्त किया है, लेकिन वे अनुसंधान में सरकारों के हस्तक्षेप को लेकर चिंतित भी हैं। यह निष्कर्ष वैश्विक संचार संस्थान एडेलमैन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट ट्रस्ट बैरोमीटर का है जिसके लिए मेक्सिको से लेकर जापान तक 28 देशों के 32,000 से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों सम्बंधित सही जानकारी प्रदान करने के लिए वैज्ञानिकों पर विश्वास जताया है। इतने ही प्रतिशत लोगों ने चाहा है कि वैज्ञानिक इन नवाचारों को पेश करने में स्वयं आगे आएं। इसके विपरीत, सही जानकारी देने के संदर्भ में लोगों ने पत्रकारों और सरकारी नेताओं पर क्रमश: 47 प्रतिशत और 45 प्रतिशत ही भरोसा जताया है। हालांकि, अध्ययन में 53 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने देश में विज्ञान के राजनीतिकरण की बात कही है, जो राजनेताओं के हस्तक्षेप की ओर इशारा करता है। विश्व स्तर पर 59 प्रतिशत का मानना है कि सरकारें और अनुसंधान वित्तपोषक एजेंसियां वैज्ञानिक प्रयासों पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। ये आंकड़े भारत में 70 प्रतिशत और चीन में 75 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 60 प्रतिशत लोगों का मानना है कि सरकारों में उभरते नवाचारों के नियमन की क्षमता का अभाव है। यह भरोसा वैज्ञानिकों के लिए एक अवसर के साथ चुनौती भी है। इस विश्वास के दम पर वैज्ञानिक प्रयास कर सकते हैं कि सरकारी नीतियां प्रमाण-आधारित बनें। इसके साथ ही वे सरकारी हस्तक्षेप और नियामक शक्तियों पर लोगों के अविश्वास सम्बंधी चिंताओं को भी संबोधित कर सकते हैं। सवाल यह उठता है कि सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए, नीतियों की दिशा सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक सरकारों के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं? कई विशेषज्ञ इस रिपोर्ट को काफी महत्वपूर्ण बताते हैं जो कोविड-19 महामारी और कृत्रिम बुद्धि के उदय जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान और नवाचार पर वैश्विक फोकस के साथ मेल खाती है। हालिया समय में दुनिया भर की सरकारें क्लस्टरिंग विश्वविद्यालयों से लेकर उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और नवीन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करने की विभिन्न रणनीतियों की तलाश कर रही हैं। एक हालिया प्रस्ताव में चिकित्सा विज्ञान में एआई की बड़ी भूमिका की वकालत की गई है लेकिन नियामक सुधारों को भी आवश्यक बताया है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में सामाजिक विज्ञान एक ऐसे उपकरण के रूप में उभरा है जिसका उपयोग नहीं किया गया है। यूके एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज़ की एक रिपोर्ट में डैटा वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, नैतिकताविदों, कानूनी विद्वानों और समाजशास्त्रियों की विशेषज्ञता की चर्चा करते हुए नीति निर्माण में सामाजिक विज्ञान को जोड़ने पर ज़ोर दिया गया है। इन क्षेत्रों के पेशेवर लोग नई प्रौद्योगिकियों, आर्थिक मॉडलों और नियामक ढांचे की ताकत और सीमाओं का आकलन कर सकते हैं और उनमें निहित अनिश्चितताओं को भी संबोधित कर सकते हैं। यदि लोगों को लगता है कि विज्ञान का राजनीतिकरण हो चुका है और सरकारें बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रही हैं, तो यह सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी समस्या है क्योंकि इससे लोगों के इस विश्वास में कमी आ सकती है कि सरकारें इन नवाचारों के लाभ उन तक पहुंचाएंगी और संभावित नुकसानों से बचाएंगी। ऐसे में वैज्ञानिकों को नवाचार के बारे में विश्वसनीय स्त्रोत बनने के अवसर है। (लेखक- संजय गोस्वामी / ईएमएस)

शब्द पहेली - 8076

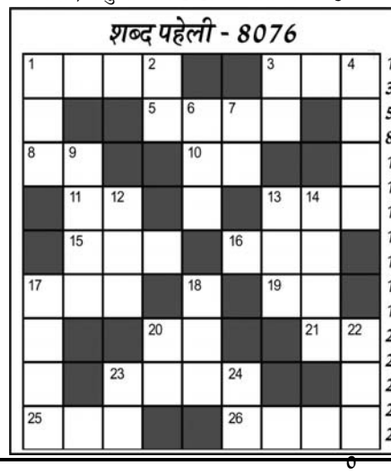

बाएँ से दाएँ

1. अँगरखा-4
3. मान-सम्मान, इज्जत-3
5. शुभाशीर्वाद, नियामत-4
8. केश-2
10. कसम, प्रतिज्ञा, वचन-2
11. बुरी आदत-2
13. मगरमच्छ-3
15. परिणाम-3
16. माँड़ी, स्टार्च-3
17. अक्षर (उर्दू-3)
19. रोम, केश-2
20. अधिकार, आरोप-2
21. सतह, स्तर, पटल-2
23. लूटपाट, डाका-4
25. सभ्यीकरण, विवेक-3
26. एक प्रसिद्ध कवि-4

ऊपर से नीचे

1. अनोखा, विचित्र, विलक्षण-3
2. नया, नवीन-2
3. इज्जत-2
4. कपोल-4
6. गमन, प्रेषित-3
7. पिता के पिता-2
9. चुनौती-4
13. गंदगी का ढ़ेर-3
14. असावधानी-4
17. जेल, कालकोठरी-4
18. शोर, ध्वनि, कंपन्न-3
20. ताप, शवदाह-2
22. यज्ञ, आहुति दान-3
23. रहस्य-2
24. जल, पानी-3

शब्द पहेली -8075 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

पेरिस ओलंपिक के बाद हॉकी से संन्यास ले लेंगे श्रीजेश

पेरिस (ईएमएस)। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के स्टार गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने कहा कि वह पेरिस ओलंपिक के बाद खेल से संन्यास ले लेंगे। इस प्रकार ये श्रीजेश का अंतिम अंतरराट्रीय टूर्नामेंट होगा। अपने करियर में अब तक 328 मैच खेलने वाले श्रीजेश का यह चौथा ओलंपिक है। 36 साल के श्रीजेश ने कई अवसरों पर भारतीय टीम की कप्तानी भी की है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और विश्व कप के साथ ही 2021 में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक में शानदार गोलकीपिंग की थी। हॉकी इंडिया ने भी श्रीजेश को उनके शानदार करियर के लिए बधाई दी है।

हॉकी इंडिया ने उन्हें जीत के साथ विदायी देने के लिए 'विन इट फॉर श्रीजेश का अभियान शुरू किया है जो खिलाड़ियों को फिर से पोडियम पर खडे होने के लिए प्रेरित करेगा। श्रीजेश ने भारतीय टीम के लिए साल 2010 में पदार्पण किया था। वह 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 2018 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम में भी शामिल रहे थे। वह 2018 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की संयुक्त विजेता टीम, भुवनेश्वर में 2019 एफआईएच पुरुष सीरीज फाइनल की स्वर्ण पदक विजेता टीम और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता टीम में भी शामिल थे।

उन्होंने भारत को एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2021-22 में तीसरे स्थान पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें साल 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 'वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार भी उन्हें मिला है। उन्हें साल 2021 और 2022 में लगातार दो बार एफआईएच 'गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। उन्होंने पिछले साल एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया था।

श्रीजेश ने कहा, 'मैं पेरिस में अपने आखिरी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा हूं, मुझे अपने करियर पर बहुत गर्व है और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मेरी अब तक की यात्रा असाधारण रही है और और मैं अपने परिवार, टीम के साथियों, सभी कोच, प्रशंसकों और हॉकी इंडिया के प्यार और समर्थन के लिए हमेशा आभारी हूं।

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ब

इधर बाइडन ने उम्मीदवारी छोड़ी,उधर खुशी से झूम उठे ओवामा, करने लगे जमकर तारीफ

वॉशिंगटन(ईएमएस)। अमेरिका में राष्ट्रपति जो भी बनेगा वो बहुत खुश होगा और जश्न मनाएगा। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओवाम खुशी से झूम रहे हैं। उनकी खुशी का कारण है,जो बाइडन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। एक दिन पहले ही ओवामा ने बाइडन से मुलाकात की थी इसके बाद माना जा रहा था कि बाइडन उम्मीदवारी छोड़ देंगे। बराक ओबामा ने कहा कि जो बाइडन अमेरिका के सबसे अहम राष्ट्रपति है, साथ ही मेरे अच्छे दोस्त हैं। आज एक बार फिर उन्होंने ये बात साबित कर दी कि वह सच्चे देशभक्त हैं। ओबामा को बतौर उपराष्ट्रपति चुनने के समय को याद करते हुए ओबामा ने कहा कि 16 साल पहले जब मैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की तलाश कर रहा था तो मुझे जो बाइडन के जनसेवा के क्षेत्र में शानदार करियर के बारे में पता था। लेकिन मैं उनकी तारीफ उनके जुझारूपन और सहानुभूति वाले चरित्र और उस विचार के लिए करता है, जिसमें वो हर नागरिक को अहम मानते हैं।

जो बाइडन की उपलब्धियां गिनाते हुए ओबामा ने कहा कि देश के कोरोना महामारी को खत्म करने, लाखों नौकरियां पैदा करने, दवाइयों की कीमत कम करने, हथियार सुरक्षा से संबंधी कानून बनाने, देश के इतिहास में जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़ा निवेश करने और हर नागरिक के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में बाइडन ने शानदार काम किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने, नाटो को फिर से संगठित करने और यूक्रेन में रूस की आक्रामकता का जवाब देने में भी बाइडन की भूमिका काफी अहम रही।अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बाइडन की तारीफ करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति बिडेन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के असाधारण संरक्षक हैं। कमांडर इन चीफ के रूप में, उन्होंने रक्षा विभाग और अमेरिकी सेना के प्रति अपनी गहन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता दिखाई है, और मैं उनके नेतृत्व के लिए बहुत आभारी हूं। हमारी विदेश नीति के सबसे महान विचारकों में से जो बाइडन भी एक हैं।

ओबामा ने कहा कि हम अनजान राहों पर आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी के नेता कुछ ऐसा करेंगे, जिससे सर्वश्रेष्ठ नामांकन सामने आएगा। मुझे विश्वास है कि जो बाइडन का एक समृद्ध, उदार और एकजुट अमेरिका का विजन अगस्त में होने वाले डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में दिखाई देगा। ओबामा बोले जो बाइडन संघर्ष से पीछे हटने वाले नेता नहीं हैं, लेकिन अब मशाल अगले दावेदार को थमाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें लगा कि यह अमेरिका के लिए सबसे सही फैसला है। यह बाइडन का देश के प्रति प्यार का सबूत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने का एलान कर दिया है। पहली डिबेट में ट्रंप के सामने कमजोर पड़ने के बाद से ही जो बाइडन पर राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने का भारी दबाव पड़ रहा था, लेकिन खुद बाइडन पीछे हटने को तैयार नहीं थे। रविवार को चौंकाते हुए बाइडन ने अचानक से पीछे हटने का एलान किया। जो बाइडन के इस फैसले की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जमकर तारीफ की है।

बीत गया आधा जुलाई..... एनसीईआरटी की किताबें नहीं आईं

मंहगे दामों में निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने को मजबूर अभिभावक

नई दिल्ली (ईएमएस)। स्कूलों और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद भी कई अभिभावकों की शिकायत है कि बाजारों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की किताबें ही नहीं मिल रही हैं। अभी जुलाई का आधे से अधिक बीत जाने के बाद बाजार में किताब नहीं आई हैं। लिहाजा पेरेंट्स को निजी प्रकाशकों से अच्छे खासे पैसे देकर किताबें खरीद रहे हैं।

एक अभिभावक ने बताया कि एनसीईआरटी की जो किताब 50 से 70 रुपए में मिल जाती है, अब उसके लिए 200 से 250 देना पड़ रहा है। निजी प्रकाशकों से ली गई ये किताबें अपेक्षाकृत काफी महंगी हैं। इससे अभिभावकों की जेब पर बोझ पढ़ रहा है। निजी प्रकाशकों की किताबें दो से तीन गुना महंगी हैं। इस साल 5 से 10 प्रतिशत कीमत बढ़ी है। कक्षा 9 से 12 की एनसीईआरटी किताब का सेट 600-1000 रूपए में आ जाता है, जबकि निजी प्रकाशकों की पुस्तक का सेट 2000 से 2500 रुपए तक मिलता है।

पढ़ाई शुरू होने के कारण अभिभावकों को मजबूरन महंगी किताबें खरीदनी पड़ रही हैं। बुक सैलर ने कहा कि पहले एनसीईआरटी की योजना थी कि सभी ग्रेड के लिए नई किताबों को लाएंगे जबकि बाद में क्लास 6 से आगे की कक्षाओं में मौजूदा करिकुलम जारी रहेगा। हर सीजन में एनसीईआरटी किताबों की कमी रहती है। यूपी की तरह सरकार को एक तय रेट फिक्स कर प्रिंटिंग की अनुमति देनी चाहिए ताकि किताबों की कमी ना होने पाए। इस कमी का फायदा उठाते हुए किताबों के दाम बढ़ा दिये जाते हैं।

भारत सुखोई विमानों को करेगा अपग्रेड, 2055 तक भर सकेंगे उड़ान

-कई खूबियों के साथ पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को देंगे टक्कर

नई दिल्ली,(ईएमएस)। भारत अपने सुखोई-30एमकेआई लड़ाकू विमानों को और शक्तिशाली बनाने में जुटा है। रक्षा मंत्रालय ने 84 सुखोई जेट को और शक्तिशाली बनाने के लिए करीब 63,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इन लड़ाकू विमानों को अपग्रेड के बाद ये सुखोई जेट अगले 30 साल तक आसमान में दुश्मनों को धूल चटा सकेंगे। इसमें जेट में अडवांस्ड रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार और मल्टी-सेंसर फ्यूजन जैसी कई खूबियां होगी। इसके बाद ये सुखोई जेट पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को टक्कर दे सकेंगे। सूत्र ने बताया कि ये अपग्रेडेड सुखोई जेट 2055 तक उड़ान भर सकेंगे।

वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं, जबकि उसे चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। हर स्क्वाड्रन में 16-18 जेट होते हैं। ऐसे में इन सुखोई जेट का अपग्रेड होना ज़रूरी है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) अगले 15 सालों में 84 सुखोई जेट को अपग्रेड करेगा। सीसीएस से मंजूरी मिलने के बाद, इसके डिजाइन और विकास में सात साल का समय लगेंगे। इसके बाद जेट को बैचों में अपग्रेड करके वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा।

भारत के पास अभी 259 सुखोई जेट हैं, जो उसकी लड़ाकू क्षमता की रीढ़ हैं। इनमें से ज़्यादातर जेट एचएएल ने रूस से लाइसेंस लेकर बनाए हैं। इसके अलावा दुर्घटनाग्रस्त हुए जेट की भरपाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए में 12 नए सुखोई जेट और उनके उपकरण खरीदे जा रहे हैं। एक अन्य सूत्र ने बताया कि अगले 15 साल में भारत के पास खुद का पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। इसकी तकनीक का इस्तेमाल पहले 84 जेट के बाद अपग्रेड किए जाने वाले सुखोई जेट में किया जाएगा।

इस अपग्रेड में सुखोई जेट में स्वदेशी 'विरूपाक्ष' एईएसए रडार लगाए जाएंगे, जो मौजूदा रडार की तुलना में 1.5 से 1.7 गुना ज़्यादा दूरी तक दुश्मन के विमानों का पता लगा सकेंगे। इसके साथ ही जेट में लंबी दूरी तक मार करने वाले एस्तरा-3 एयर-टू-एयर मिसाइल भी लगाए जाएंगे, जो 350 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं। वायुसेना अभी 100 किलोमीटर तक मार करने वाली एस्तरा-1 मिसाइलों को शामिल कर रही है। वहीं डीआरडीओ 160 किमी तक मार करने वाली एस्तरा-2 और सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रणोदन वाली एस्तरा-3 मिसाइल विकसित कर रहा है।

एक सूत्र ने बताया कि फ्लाई-बाय-वायर सिस्टम को छोड़कर अपग्रेड किए गए सुखोई जेट के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स स्वदेशी होंगे। इसमें बेहतर एल्गोरिदम वाले तीनों मिशन कंप्यूटर शामिल हैं। कुल मिलाकर, अपग्रेड किए जाने वाले 51 सिस्टम में से 30 एचएएल द्वारा, 13 डीआरडीओ द्वारा और आठ निजी क्षेत्र द्वारा बनाए जाएंगे। अभी 40 सुखोई जेट को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले जाने के लिए अपग्रेड किया है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता को पहले ही 290 से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया है और जल्द ही 800 किमी वाले वर्जन को भी शामिल किया जाएगा।

नीट में आज फिर सुनवाई ..... आईआईटी दिल्ली को दिया ये काम

-तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने का आदेश

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर सुनवाई कर सोमवार को आईआईटी दिल्ली से कहा है कि वे नीट के विवादित प्रश्न से जुड़े विषय के तीन विशेषज्ञों की समिति बनाए जो इसके सही उत्तर पर राय देगी। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के विवादित प्रश्न के सही उत्तर पर राय बनाने के लिए संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने का आदेश दिया है। कुछ छात्रों ने प्रश्न संख्या 19 के दो विकल्पों के लिए अंक देने के एनटीए के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता छात्र का कहना है कि नेगेटिव मार्किंग के डर से उस प्रश्न को छोड़ दिया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई शुरू होते ही पूछा कि नीट के सेंटर व शहर आधिरित रिजल्ट से क्या निकला? याचिकाकर्ता के वकील नरेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हमने डेटा पर आधारित नोट सब्मिट कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि नीट का पेपर परीक्षा के दिन 5 मई से दो दिन पहले ही लीक हो चुका था। उन्होंने कहा कि नीट का पेपर 3 मई को या उससे पहले लीक हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के बयानों से साफ होता है कि नीट पेपर लीक 4 मई से पहले हुआ। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ नीट को लेकर दायर 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की।

जम्मू में शौर्य चक्र विजेता के घर आतंकी हमला

जम्मू (ईएमएस)। जम्मू के राजौरी के घोंधा में सोमवार सुबह आतंकियों ने एक शौर्य चक्र विजेता के घर पर हमला किया। घटना सुबह 3:10 बजे हुई। हमले की खबर लगते ही 63 आरआर आर्मी कैंप से आई टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है।

शौर्य चक्र विजेता की पहचान परशोत्तम कुमार के रूप में हुई है। उन्हें पिछले महीने दो आतंकियों को मारने के बाद यह सम्मान मिला था। परशोत्तम कुमार विलेज डिफेंस गार्ड भी हैं। आतंकी हमले में एक जवान और परशोत्तम कुमार के चाचा घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शरणार्थियों को शरण देने का फैसला केंद्र सरकार करती है कोई भी राज्य नहीं

-बांग्लादेशियों को शरण देने के ममता बनर्जी के बयान पर रविशंकर भड़के

नई दिल्ली,(ईएमएस)। पश्चिम बंगाल की तेज तर्रार सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लोग अगर बंगाल आना चाहेंगे तो वह उन्हें शरण देंगी। इस पर सियासत शुरु हो गई है। ममता के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह वहीं ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने सीएए के तहत हिंदू, सिख और पारसियों को मिलने वाली नागरिकता का विरोध किया था।

रविशंकर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि बांग्लादेश के लोगों को वह बंगाल में शरण देंगी। यह ममता वहीं हैं, जिन्होंने सीएए के मुद्दे पर कहा था कि हम किसी भी हिंदू, सिख और पारसी शरणार्थियों को बंगाल में शरण नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने हमेशा ही सीएए का विरोध किया है। शरणार्थियों को शरण देने का फैसला केंद्र सरकार करती है। कोई भी राज्य ऐसा फैसला नहीं ले सकता है। उन्होंने 1971 युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान भी शरणार्थियों को शरण देने का फैसला केंद्र सरकार ने ही किया था। बांग्लादेश में जो भी चल रहा है, वह उसका आंतरिक मामला है। ममता ने कहा कि हिंदुस्तान के संबंध बंगाल के साथ अच्छे हों, इस बयान का क्या मतलब है।

अर्जेंटीना में डेंगू के करीब साढ़े पांच लाख मामले दर्ज

ब्यूनस आयर्स (ईएमएस)। अर्जेंटीना में इस साल अब तक डेंगू के पांच लाख 27 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 3.2 गुना अधिक मामले दर्ज हुए हैं, हालांकि हाल में मामलों में कमी आई है।

मंत्रालय केनए राष्ट्रीय महामारी विज्ञान बुलेटिन के अनुसार, इस वर्ष के पहले 28 हफ्तों में स्वास्थ्य अधिकारियों ने 527,517 मामले दर्ज किए।

वाइडेन चुनाव से पीछे हट गए लेकिन ट्रंप को चुनौती भी दे गए

वॉशिंगटन(ईएमएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडन हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते थे। उनकी इच्छा थी एक बार फिर राष्ट्रपति बनें,लेकिन उनकी सेहत और इंटरनली प्रेशर के चलते उन्हे चुनावी रेस से बाहर होना पड़ा है। बाइडेन ने पीछे हटने का ऐलान करते हुए कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाकर एक चुनौती जरुरी खड़ी कर दी है। अब देखना यह है कि कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार बनेंगी या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप को रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस बीच ट्रंप और उनके समर्थकों का दावा है कि कमला हैरिस को हराना उनके लिए और भी आसान होगा। हालांकि यह उतना आसान भी नहीं होने जा रहा है। बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव से हटने ऐलान के कुछ ही देर बाद ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस को हराना और भी आसान होगा। इसको लेकर ट्रंप समर्थकों की अपनी दलील है। उनका कहना है कि जो बाइडेन की तमाम नीतियों के लिए कमला हैरिस ही जिम्मेदार हैं। एक तीस सेकंड का ऐड भी चलाया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि कमला हैरिस जानती थीं कि जो बाइडेन अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने काम किया और देखिए क्या है। बॉर्डर पर घुसपैठ हो रही है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है और अमेरिकियों के सपनों का अंत हो चुका है। असल में बाइडेन के कार्यकाल में सीमा से घुसपैठ, बढ़ती महंगाई और महंगे होम लोन कुछ बेहद चर्चित मुद्दे हैं।

जो बाइडेन के सामने डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीजें आसान हो गई थीं। ट्रंप के ऊपर हुए हमले के बाद सहानुभूति की लहर भी उनके पक्ष में जा रही थी। लेकिन अगर कमला हैरिस के रूप में नया विपक्षी ट्रंप के सामने आता है तो उन्हें रणनीतियों में भी बदलाव करना होगा। इस बीच ट्रंप समर्थक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ने भी बदलते सिनैरियों के हिसाब से जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उसका कहना है कि अब वह ट्रंप विरोधी टीवी ऐड्स को हटाने वाला है। इसकी जगह, एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और पेन्सिलवेनिया में नए विज्ञापन चलाए जाएंगे, जो कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने विरोधियों पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के लिए जाने जाते हैं। शनिवार को भी उन्होंने कुछ इसी अंदाज में कमला हैरिस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि मैं तो उसे लॉफिंग कमला कहता हैं। आपने कभी ऐसी हंसी देखी है? वह क्रेजी है।

इस सप्ताह 16 नई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। इस सप्ताह 16 नई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी जिससे लोगों को शुरूआती दौर में ही निवेश का मौका मिलेगा। सप्ताह के शुरूआत में एसएमई (छोटी, मझली कंपनिया) सेक्टर की 8 कंपनियों के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। इन कंपनिया का बाजार से 809 करोड़ रुपये जुटाने का अनुमान है। निवेशकों को इनमें कम से कम 13,500 रुपये निवेश करना होगा। इसके साथ ही शेयर बाजार में 8 नई कंपनियां लिस्ट होंगी। ब्लूमबर्ग के अनुसार इस साल भारतीय शेयर बाजार में जो नए शेयर लिस्ट हुए, उन्होंने औसतन 57 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं पूरे ऐशिया प्रशांत में नए शेयरों ने 32 फीसदी का रिटर्न दिया है। 2024 में आए नए आईपीओ 12 गुना अधिक सब्सक्राइब हुए क्योंकि रिटेल निवेशक इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस सप्ताह सोमवार को श्री एम पेपर बोर्ड, प्राइजर विजटेक, एविया कमो. और सिटी पॉली प्लास्ट शेयर मार्केट में लिस्ट होंगी। वहीं मंगलवार को टुनवाला ई-मोटरास और बुधवार को मैकाब्स टेक्नो और कटारिया इंडस्ट्रीज लिस्ट होंगी। शुक्रवार को आखिरी कारोबारी दिन में सैनस्टार का खाता खुलेगा। 8 में से 4 आईपीओ के लिए 2 लाख से ज्यादा का निवेश करना होगा। बाजार में कंज्यूमर, हेल्थ केयर और टेक सेक्टर की कंपनियां आईपीओ लाने में सबसे आगे हैं। ब तक भारतीय बाजार में आई 36 बड़ी कंपनियों ने रिटेल निवेशकों से 92,000 करोड़ रुपये जुटाए है। इस दौरान केवल आईपीयो ने करीब 32,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। अगले छह महीनों में हुंडई इंडिया, विशाल मेगामार्ट समेंत 15 बड़ी कंपनिया आईपीओ लाएंगी।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद सेंसेक्स 103 , निफ्टी 22 अंक नीचे आया

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। बजट से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा बैंक में भारी बिकवाली रही। इससे इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी नीचे आये। वहीं दुनिया भर के बाजारों के मिले कमजोर संकेतों से भी निवेशकों से सतर्कता बरती।

दिन भर के गिरावट के साथ 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 102.57 अंक करीब 0.13 फीसदी नीचे आकर 80,502.08 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 21.65 अंक तकरीबन 0.09 फीसदी नीचे आकर 24,509.25 पर बंद हुआ।

आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 शेयर नुकसान के साथ ही नीचे आकर बंद हुए। कोटक बैंक, रिलायंस, आईटीसी, एसबीआई और एचसीएल टेक सेंसेक्स के सबसे अधिक नुकसान वाले शेयर रहे। वहीं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, नेस्ले इंडिया, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्लयू स्टील, टाइटन और अदाणी पोर्ट्स के शेयर नुकसान में रहे।

वहीं दूसरी ओर सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 शेयर लाभ के साथ ही ऊपर आकर बंद हुए। एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील और एंडएमएम सेंसेक्स के शीर्ष पांच लाभ वाले शेयर रहे। इसके अलावा, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, एलएंडटी, मारुति, इंफोसिस, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा और एचयूएल के शेयर लाभ में रहे।

एशियाई बाजारों में, सियोल, टोक्यो और शंघाई निचले स्तर पर बंद हुए, जबकि हांगकांग सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुआ। दोपहर के सत्र में यूरोपीय बाजार बढ़त पर कारोबार कर रहे थे। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 1,506.12 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी। इससे पहले आज सुबह वै?श्विक बाजारों से ?मिले खराब संकेतों की वजह से सप्ताह के पहले कारोबारी ?दिन सोमवार को घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत ?गिरावट के साथ हुई। बीएसई सेंसेक्स 463 अंक गिरकर 80,141 अंकों पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी50 सूचकांक 147 अंकों की गिरावट के साथ 24,383 अंकों पर आ गया। इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स ने 81,587 और निफ्टी ने 24,853 का स्तर छुआ। हालांकि, इसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। सेंसेक्स 738 अंक की गिरावट के साथ 80,604 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 269 अंक की गिरावट रही, ये 24,530 के स्तर पर बंद हुआ था।

म्यांमार में बचाए गए 8 भारतीय नागरिक

यंगून (ईएमएस)। यंगून में भारतीय दूतावास ने कहा कि म्यांमार के म्यावाडी के हापा लू क्षेत्र में नौकरी घोटाले के शिकार आठ भारतीयों को बचाया गया है। भारतीय दूतावास ने उस देश में नौकरी की तलाश कर रहे भारतीय नागरिकों से सावधान रहने को कहा है, ताकि वे फर्जी या अवैध रोजगार के लालच में न फंसें। दूतावास ने कहा कि हापा लू, म्यावाड्डी में एक घोटाला केंद्र के पीड़ित 8 भारतीय नागरिकों को बचाया गया और सुरक्षित रूप से म्यांमार पुलिस/आव्रजन को सौंप दिया गया।

पिछले महीने एक सलाह में दूतावास ने कहा कि म्यांमार-थाईलैंड सीमा पर म्यावाडी क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट सक्रिय है और भारतीयों से क्षेत्र में नौकरी की पेशकश लेने से पहले सावधानी बरतने का आग्रह किया।दूतावास ने कहा कि म्यांमार-थाईलैंड सीमा पर म्यावाड्डी क्षेत्र में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट का शिकार बनने वाले भारतीय नागरिकों की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

चुनाव अभियान के बीच में राष्ट्रपति की उम्मीदवारी छोड़ना अमेरिका में पहले भी हो चुकी है इस तरह की घटना

वाशिंगटन,(ईएमएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक घोषणा ने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया भी चौंका दिया। उन्होंने घोषणा कि वह राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन की घोषणा के बाद ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर सामने आने की चर्चा जोरों पर है तो वहीं बाइडेन ने भी उन्हें अपना समर्थन दे दिया है।

इसी बीच अमेरिकी में राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास पर नजर डालें तो यह पहली बार नहीं है कि पद पर रहते हुए किसी राष्ट्रपति ने दूसरी बार सत्ता में वापसी करने का विचार चुनाव अभियान के बीच ही छोड़ दिया हो और खुद को इस रेस से बाहर कर लिया हो। रविवार देर रात को जिस तरह का फैसला जो बाइडेन ने लिया उस तरह की घटना अमेरिका के सियासी इतिहास में साल 1968 में भी हो चुकी है।

1968 में, राष्ट्रपति चुनाव के बीच राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने उम्मीदवारी से पीछे हटने का फैसला करके सबको चौंकाया था। उन्होंने यह घोषणा वियतनाम युद्ध के बीच में की थी। 1968 में जॉनसन ने महसूस किया था कि वह पार्टी पर नियंत्रण खो रहे हैं और पार्टी के अंदर ही चार विरोधी गुट बन गए थे। वियतनाम युद्ध पर अलग-अलग रुख उन मुद्दों में से एक था जिसने पार्टी को बांट दिया था, वहीं जॉनसन को युद्ध जीतने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसके अलावा वह पार्टी को एकजुट बनाए रखने में भी असमर्थ थे। इसके अलावा जॉनसन अपने गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित थे। वह यह भी मान कर चल रहे थे कि वह एक और कार्यकाल तक जीवित नहीं रह पाएंगे।

28 मार्च को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और राजनीतिक पकड़ के ढीली होने के साथ राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने पर विचार किया और जोसेफ ए. कैलिफ़ानो जूनियर और हैरी मैकफरसन के साथ इस पर चर्चा की. इस मुलाकात के तीन दिन बाद जॉनसन ने खुद को राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से अलग करने का ऐलान कर दिया था।

इसके बाद उपराष्ट्रपति रहे ह्यूबर्ट हम्फ्री को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन रिपब्लिकन उम्मीदवार रिचर्ड निक्सन ने उन्हें हरा दिया और राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। 5 नवंबर 1968 को रिपब्लिकन उम्मीदवार रिचर्ड निक्सन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता और अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए थे।

कनाडा में रोजगार के लिए भटक रहे भारतीय, वतन वापसी की कर रहे तैयारी

टोरंटो(ईएमएस)। कनाडा में भी रोजगार की समस्या है। यहां भारतीयों को इस समय रिकॉर्ड बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। कनाडा में हाल ही में बसे आप्रवासियों के लिए बेरोजगारी दर जून में 12.6 प्रतिशत थी। यह पिछले 10 वर्षों का सबसे खराब बेरोजगारी स्तर है। कनाडा में स्थायी नागरिकता हासिल करने वालों में सबसे ज्यादा लोग भारतीय हैं। इसलिए भारतीयों पर ही इस बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा पड़ने की संभावना है। हालांकि मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि पिछले आठ महीनों में कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों से उनकी समस्या हल नहीं होगी और कनाडा से रिवर्स माइग्रेशन अभी दूर की बात है।

रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ब्रैम्पटन में कनाडाई पंजाबी सांस्कृतिक सोसायटी के एक सेमिनार में पंजाबी विश्वविद्यालय के रिटायर प्रोफेसर कुलदीप सिंह ने कहा कि कनाडा में छात्रों की संख्या में कमी आई है लेकिन रिवर्स माइग्रेशन तभी संभव है जब भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति कनाडा से बेहतर होगी। इस स्थिति की फिलहाल कोई संभावना बनती नहीं दिख रही है। कुलदीप सिंह ने कहा कि कोई की शख्स तभी वापस लौटने की कल्पना कर सकता है, जब उसे अपने देश में ज्यादा असवरों दिखे। यह अभी भी एक कल्पना है, वास्तविकता से बहुत दूर है। विश्व विकास रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रोफेसर सिंह ने कहा कि अंतरा राष्ट्रीय छात्रों के रूप में दुनियाभर में जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2000 में 2 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 41 प्रतिशत हो गई है। कनाडाई आव्रजन परामर्श के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय छात्रों के कनाडा प्रवास में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केवल 2019 में 198,235 छात्र भारत से कनाडा आए और इसमें से 71 प्रतिशत अनुपात पंजाब से थे।

कनाडा की राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी स्टैटिस्टिक कैनेडा के अनुसार 12.6 प्रतिशत की बेरोजगारी दर 2023 से चार प्रतिशत कम है। कनाडाई मूल के लोगों में बेरोजगारी 5.5प्रतिशत है। साल 2023 में यह 5प्रतिशत थी। ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के अनुसार, नए आंकड़े बताते हैं कि आप्रवासियों के बीच बेरोजगारी दर 2014 के बाद से सबसे ज्यादा है। आप्रवासियों में बढ़ती बेरोजगारी से भारतीयों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना इसलिए है क्योंकि हाल के वर्षों में कनाडा की सबसे ज्यादा नागरिकता भारतीयों को ही मिली है। साल 2023 में कनाडा ने 4,71, 810 लोगों को स्थायी नागरिकता दी। इनमें से 1,39,785 या लगभग 30प्रतिशत भारतीय थे। इमिग्रेशन, रेफ्युजीज़ एंड सिटीजनशिप कैनेडा के आंकड़ों के अनुसार, 2019 के बाद से कनाडा आए 18,41,250 नए स्थायी निवासियों में से 5,14,435 भारतीय थे। स्टैटिस्टिक कैनेडा ने एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया कि जून 2024 में 14 लाख बेरोजगार लोग थे, जो पिछले महीने से 42,000 (+3.1 प्रतिशत) ज्यादा हैं। कनाडा में कंपनियां उच्च ब्याज दरों से जूझ रही हैं। इसी वजह से वे पिछले दो सालों में नियुक्तियां करने में झिझक रही हैं। आप्रवासियों की भारी आमद के कारण कनाडा की जनसंख्या में वृद्धि भी हुई है।

कमला का समर्थन कर रामास्वामी ने भारतीय-अमेरिकियों के प्रतिनिधित्व को बड़ी छंलाग

वाशिंगटन (ईएमएस)। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक नेता अश्विन रामास्वामी ने पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया। रामास्वामी ने कहा,''यह (कमला का राष्ट्रपति चुना जाना) भारतीय-अमेरिकियों और एएपीआई (एशियाई अमेरिकी और प्रशांत द्वीप समूह निवासी) के प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बड़ी छलांग होगा।''

रामास्वामी की यह टिप्पणी तब आई, जब बाइडन ने चुनाव लड़ने में असमर्थता जताकर डेमोक्रेटिक पार्टी की नई उम्मीदवार के रूप में भारतीय-अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस के नाम की सिफारिश की।

रामास्वामी ने कहा, ''उपराष्ट्रपति कमला अमेरिका की पहली भारतीय-अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचेंगी। यह अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी और एएपीआई समुदाय के प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बड़ी छलांग होगा और मेरे जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा साबित होगा। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन हैरिस की तरह मेरी मां भी चेन्नई के बेसेंट नगर से हैं, जो मेरे लिए बेहद खास बनाता है। रामास्वामी ने कहा कि वह राष्ट्रपति बाइडन के शानदार नेतृत्व के लिए उनके आभारी हैं और उनके नक्शेकदम पर चलते हुए अगले डे

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का प्रो-एक्टिव दृष्टिकोण : बांग्लादेश में फँसे 14 गुजराती छात्र सुरक्षित स्वदेश लौटे

गांधीनगर 22 जुलाई, 2024 : बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति में वहाँ फँसे गुजरात के छात्रों में से 14 छात्र स्वदेश लौट आए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशानिर्देशन में राज्य सरकार ने भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ तत्काल समन्वय स्थापित किया, जिसके चलते ये 14 गुजराती छात्र सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। श्री पटेल ने बांग्लादेश में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गए विद्यार्थियों को वहाँ भड़की हुई हिंसा व अन्य घटनाओं के बीच से सुरक्षित अपने माता-पिता व परिवार तक पहुँचाने की व्यवस्था के लिए राज्य के प्रवासी गुजराती प्रतिष्ठान (एनआरजी फाउंडेशन) को तत्काल समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के चलते एनआरजी फाउंडेशन ने बांग्लादेश में फँसे विद्यार्थियों का विवरण प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9978430075 घोषित किया है। इतना ही नहीं; ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावक व परिजन अपने बच्चों की जानकारी प्राप्त कर सकें; इसके लिए ई-मेल आईडीहिंदिर्ल्यूदहुर्ल्यूदन्गह पर भी विवरण मंगवाना शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशानिर्देशन में राज्य सरकार के इस प्रो-एक्टिव दृष्टिकोण के फलस्वरूप विद्यार्थियों के अभिभावकों-परिजनों ने एनआरजी फाउंडेशन का संपर्क कर विवरण दिया था। इस विवरण के आधार पर एनआरजी फाउंडेशन ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ सम्पर्क साधा और जिन 25 के करीब विद्यार्थियों का संपर्क हुआ, उन्हें गुजरात लाने की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कीं।

इन फलदायी प्रयासों के परिणामस्वरूप फिलहाल भरूच जिले के 7, अहमदाबाद व भावनगर के 2-2 और अमरेली, मेहसाणा तथा पाटण के 1-1 सहित कुल 14 छात्र बांग्लादेश से सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। श्री पटेल के निरंतर मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ परामर्श में रहते हुए शेष 11 छात्रों को वापस लाने की कवायद भी शुरू की है।

केन्द्रीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की स्थिति के संदर्भ में एक एडवाइजरी जारी कर वहाँ बसने वाले भारतीय समुदाय के लोगों तथा छात्रों से लोकल ट्रैवल न करने तथा घर से बाहर कम से कम निकलने का अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में किसी भी प्रकार की सहायता या तत्काल आवश्यकता लगने पर बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायुक्त तथा सहायक उच्चायुक्त के 24 घण्टे कार्यरत फोन नंबर घोषित किए हैं।

ये नंबर निम्नानुसार हैं : भारतीय उच्चायोग, ढाका, +880-1937400591 (व्हॉट्सएप भी) ,* सहायक भारतीय उच्चायोग, चटगाँव ,+880-1814654797/+880-1814654799 (व्हॉट्सएप भी) ,* सहायक भारतीय उच्चायोग, राजशाही ,+880-1788148696 (व्हॉट्सएप भी), * सहायक भारतीय उच्चायोग, सिलहट ,+880-1313076411 (व्हॉट्सएप भी) ,* सहायक भारतीय उच्चायोग, खुलना ,+880-1812817799 (व्हॉट्सएप भी)

मुख्यमंत्री ने भूटान नरेश और प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से किया स्वागत

गांधीनगर 22 जुलाई : गुजरात के तीन दिवसीय दौरे के दौरान अहमदाबाद पहुंचे भूटान नरेश श्री जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक तथा प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोबगे का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया।

इस अवसर पर प्रोटोकॉल मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, भूटान में भारत के राजदूत श्री सुधाकर दलेला, राज्य के मुख्य सचिव श्री राज कुमार, राज्य पुलिस महानिदेशक श्री विकास सहाय, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अनुराग श्रीवास्तव, अहमदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त श्री अजय चौधरी, चीफ प्रोटोकॉल अधिकारी श्री ज्वलंत त्रिवेदी, अहमदाबाद कलेक्टर सुश्री प्रवीणा डी.के. सहित कई उच्च अधिकारियों ने गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया।

हवाई अड्डे पर महानुभावों द्वारा भूटान नरेश श्री जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक तथा प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोबगे के स्वागत के बाद गुजरात की विशिष्ट परम्परा के अनुसार गरबा नृत्य के साथ उनका स्वागत-सम्मान किया गया। इस अवसर पर गरबा और ढोल के नाद के साथ गुजरात की रंग-बिरंगी संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई।

24 घंटों में राज्य की 150 तहसीलों में बारिश, अब तक मौसम की 40 फीसदी से अधिक औसत बारिश

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 150 तहसीलों में बारिश हुई है, उसमें सबसे अधिक दक्षिण गुजरात के उमरगाम में 8 इंच बारिश दर्ज हुई राज्य में मौसम की अब तक 40 फीसदी से अधिक बारिश हो चुकी है हालांकि उत्तर-मध्य गुजरात में अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है स्टेट इमर्जेंसी ऑपरेशन सेंटर के 22 जुलाई 2024 को सुबह 6 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सीजन की कुल औसत बारिश का 40 प्रतिशत से अधिक रिकार्ड की गई।

जिसमें सौराष्ट्र जोन में सबसे ज्यादा 59 फीसदी बारिश हुई है जबकि कच्छ जोन में कुल 51 फीसदी, दक्षिण गुजरात में 45 फीसदी, उत्तरी गुजरात में 23 फीसदी और पूर्व-मध्य गुजरात में 24 फीसदी बारिश भी सीजन की कुल औसत बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में हुई बारिश की बात करें तो वलसाड के उमरगाम में सबसे अधिक 8 इंच, सूरत के कामरेज, पलसाणा और सूरत शहर में 6 इंच, वापी के निझर में 5 इंच, सूरत के महुवा में 5 इंच और भरुच जिले के अंकलेश्वर में 5 इंच बारिश रिकार्ड हुई राज्य की पारडी, ओलपाड, बारडोली, पाटन-वेरावल, गणदेवी, खंभात समेत 6 तहसीलों में 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई वहीं उमरपाड़ा, कपराडा, जामजोधपुर, वालोड, धोलका, जामनगर, विसावदर, जलालपोर, वलसाड, वापी और खेरगाम समेत 11 तहसीलों में 3 इंच, डोलवण, सूत्रपाडा, घोघा, चीखली, वालिया, धंधुका, नेत्रंग, माणावदर, राजुला, व्यारा, भरुच, मांगरोल और नांदोद समेत 13 तहसीलों में 2 इंच, तलाला, बावला, चौर्यासी, सागबारा, तारापुर, पोरबंदर, डेडियापाडा, मांडवी, करजण और धरमपुर समेत 10 तहसीलों में डेढ़ इंच से अधिक बारिश दर्ज हुई इसके अलावा सोनगढ़, धोराजी, तिलकवाडा, झगडिया, केशोद, जूनागढ़, भेंसाण, वंथली समेत 8 तहसीलों में 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई गरुडेश्वर, डांग आहवा, कल्याणपुर, लालपुर, धारी, सिनोर, ऊना, भावनगर, वांसदा, जोडिया, कोडीनार, वघई, सायला, नडियाद, अमरेली, खेडा और सोजित्रा समेत कुल 17 तहसीलों में आधा इंच से बारिश दर्ज हुई इस बीच आज सुबह से राज्य की 69 तहसीलों में बारिश हुई है जिसमें सबसे अधिक गिर सोमनाथ में दो घंटे के भीतर पौने तीन इंच बारिश दर्ज हुई है जूनागढ़ के केशोद में ढाई इंच बारिश होने की खबर है

सूरत में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बाढ़ से तबाही

सरथाना, वराछा, अठवागेट, कतारगाम, उधना, शंदेर, अडाजण, वेसु और सचिन में पानी भर गया, जिससे कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया

सूरत, २२ जुलाई । इस समय गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है । सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है । रविवार रात को सूरत में भी भारी बारिश हुई जिसके कारण सूरत के कई इलाकों में पानी भर गया है । खटोदरा इलाके में दुकानों और घरों में पानी घुस गया । इसके अलावा निचले इलाकों में भी भूस्खलन की हद तक पानी भर गया है । रविवार शाम से ही सूरत में बारिश शुरू हो गई । रविवार को छुट्टी होने के कारण परिवार के साथ बाहर निकले लोगों को तेज बारिश के कारण परेशानी हुई । सूरत के सरथाना, वराछा, अठवागेट, कतारगाम, उधना, शंदेर, अडाजण, वेसु और सचिन में पानी भर गया, जिससे कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया ।

रविवार को हुई भारी बारिश से सूरत में पानी भर गया, वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है । सूरत में रविवार सुबह से बारिश हो रही थी लेकिन बारिश नहीं हुई । रविवार को छुट्टी होने के कारण शाम को लोग परिवार के साथ बाहर भी निकले । मूसलाधार बारिश होते ही लोगों के गिरने की बारी आ गई । इसके अलावा भारी बारिश के कारण पानी भर गया और सड़कों पर पानी भर गया. जिसके कारण ट्रैफिक जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ा ।

भारी बारिश के कारण आज सूरत शहर और वराछा क्षेत्र को जोड़ने वाली सूर्यपुर गरनाले में बरसात का पानी जमा हो गया। वराछा निवासियों के लिए शहर में प्रवेश करने या रेलवे स्टेशन जाने का मुख्य मार्ग है, लेकिन आज व्यस्त समय में यातायात के दौरान गरनाले में भारी जलजमाव हुआ। इसके कारण यह गरनाला वाहन चालकों के लिए बंद कर दिया गया है। हालाँकि, कुछ लोग जिन्होंने वाहन ले जाने की कोशिश की, वे बमुश्किल बाहर निकल सके क्योंकि वाहन रुक गया था।

इसी तरह, डुंभाल और लिंबायत में भी रेलवे पटरीयों के नीचे बनाए गए सबवे पानी से भर जाने के कारण वाहनों के आवागमन के लिए बंद हैं। इस गरनाले के बंद होने के कारण उस सड़क पर यातायात की भारी समस्या उत्पन्न हो गई। लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक सड़कों का उपयोग करना पड़ा।

सूरत के अठवागेट, पार्ले प्वाइंट, पिपलोद, मजूरगेट, उधना दरवाजा, वेसू समेत अन्य इलाकों में भारी बारिश हुई. इसके अलावा शंदेर, अडाजण, चौक बाजार, नानपुरा, उधना, भेस्तान, पांडेसरा, दिल्ली गेट और कतारगाम समेत इलाकों में हवा के साथ बारिश हुई । उधर, सूरत जिले में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है । फिलहाल सूरत जिले में कुल २२ सड़कें बंद हैं । कामरेज तालुक में १, पलसाना तालुक में ६, बारडोली तालुक में १० और मांडवी तालुक में ५ बारिश के पानी में बह गए हैं । वहीं सूरत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के कारण पेड़ भी उखड़ गए. तेज हवाओं के कारण ३९ पेड़ टूट गए । अग्निशमन विभाग की टीम ऐसे पेड़ों को हटाने में जुटी रही ।

राजधानी गांधीनगर में IAS की पत्नी ने जहर खाकर दी जान

गांधीनगर, २२ जुलाई । गुजरात के एक आईएएस अधिकारी की अलग रह रही पत्नी ने रविवार को गांधीनगर में अधिकारी के घर के दरवाजे पर जहर खाकर दम तोड़ दिया । पिछले महीने यह आईएएस की पत्नी अपने गृहनगर तमिलनाडु के एक गैंगस्टर के साथ भाग गई थी । वहां एक बच्चे के अपहरण के मामले में भी वह शामिल थी । महिला का नाम सूर्या जे (४५) था । जहर खाने के बाद उसे इलाज के लिए की गुजरात की राजधानी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई । पुलिस के अनुसार, सूर्या ने शनिवार सुबह जहरीला पदार्थ निगला था । वह अपने पति रंजीत कुमार जे के घर पहुंची थी । यहां महिला से नाराज उसके पति ने अपने यहां के स्टाफ को निर्देश दिया था कि वे उसे घर में न आने दें ।

घटना गांधीनगर के सेक्टर-१९ की है । रंजीत कुमार गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (जीईआरसी) के सचिव हैं । एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'रंजीत कुमार शनिवार को सूर्या के साथ तलाक की अर्जी को अंतिम रूप देने के लिए बाहर गए थे ।'

रंजीत ने स्टाफ को साफ कहा था कि सूर्या को किसी भी सूरत में अंदर न आने दें । वह यहां पहुंची और जबरन अंदर जाने का प्रयास किया लेकिन कर्मचारियों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया । इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने (सूर्या) जहर खा लिया और १०८ (एम्बुलेंस हेल्पलाइन) पर कॉल किया । गांधीनगर के एसपी रवि तेजा वासमसेट्टी ने कहा कि सूर्या जे के पास पुलिस को तमिल में लिखा एक कथित सुसाइड नोट मिला है, लेकिन उन्होंने विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया । पुलिस ने कहा कि जे सूर्या गैंगस्टर के साथ मदुरै के एक १४ वर्षीय लड़के के अपहरण में शामिल थी । हो सकता है कि मामले में तमिलनाडु पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए सूर्या अपने पति के घर गई होगी ।

इस मामले में सूर्या का नाम उसके कथित प्रेमी और स्थानीय गैंगस्टर हाई कोर्ट महाराजा और उसके सहयोगी सेंथिल कुमार के साथ सामने आया । उन्होंने कथित तौर पर बच्चे की मां के साथ पैसे के विवाद में ११ जुलाई को लड़के का अपहरण कर लिया था । उन्होंने उसकी मां से २ करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी, लेकिन मदुरै पुलिस ने लड़के को बचाने में कामयाबी हासिल की । इसके बाद पुलिस ने सूर्या सहित सभी लोगों की तलाश शुरू कर दी ।

इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सूर्या ने रंजीत कुमार को छोड़ दिया था और करीब नौ महीने पहले हाई कोर्ट महाराजा नाम के गैंगस्टर के साथ भाग गई थी । एसपी वासमसेट्टी ने अपहरण मामले को एक कारक बताया । अधिकारी ने कहा, 'मुझे रिपोर्टों से पता चला कि उस पर (सूर्या) मदुरै में अपहरण का आरोप था, जिसके कारण उसे यह चरम कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा ।'

चांदीपुरा वायरस से मृतकों की संख्या हुई ३३

अहमदाबाद, २२ जुलाई । राज्य में चांदीपुरा वायरस का कहर जारी है । सरकार अलर्ट मोड पर कार्रवाई में जुटी है । गांव से लेकर शहर तक यह वायरस पैर पसार चुका है । राज्य में मानसून की बरसात इस वायरस को फैलाने में मददगार है, इसलिए प्रशासन कई स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है । हॉस्पिटलों में व्यवस्था स्टैंडबॉय रखी गई है, तो कई जगहों पर विशेष वार्ड में बच्चों का इलाज किया जा रहा है ।

संक्रमण से यह बीमारी नहीं फैलती है, इस वजह से प्रशासन इसकी मूल वजह सैंड मक्खी को नियंत्रित करने में जुटा है । सोमवार को ३ बच्चों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर ३३ हो गई । सोमवार को बनासकांठा के सुइगाम, राजकोट के गोंडल के राणसिकी और देवभूमि द्वारका जिले में १-१ बच्चे की मौत हो गई । इसके साथ ही चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध केस की संख्या बढ़कर ८४ हो गई है । जानकारी के अनुसार राजकोट जिले की गोंडल तहसील के राणसिकी गांव में ७ वर्षीय बालक की तबियत बिगड़ने पर उसे रविवार को राजकोट के जनाना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था । बच्चे की सभी तरह की जांच कराई जा रही थी लेकिन रिपोर्ट आने से पूर्व ही सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई । गोंडल के राणसिकी गांव के सरपंच घनश्याम काछडिया ने एक बच्चे की मौत उसके घर में और दूसरे बच्चे की मौत हॉस्पिटल में होने की जानकारी दी है । इस तरह उन्होंने दो मौत का दावा किया है । इसके अलावा बनासकांठा के सुईगांव में चांदीपुरा के संदिग्ध मरीज की सोमवार सुबह मौत हो गई है । सूरत में १ केस और मौत ०, राजकोट में ४ केस और मौत ३, साबरकांठा में ८ केस और मौत २, अरवल्ली में ६ केस और मौत ३, महीसागर में २ केस और मौत १, खेडा में ६ केस और मौत १, मेहसाणा में ६ केस और मौत २, सुरेन्द्रनगर में ३ केस और मौत १, अहमदाबाद में ६ केस और मौत ३, गांधीनगर में ५ केस और मौत १, पंचमहाल में ११ केस और मौत ४, जामनगर में ५ केस और मौत ०, मोरबी में ४ केस और मौत ३, जामनगर में ३ केस और मौत १, छोटाउदेपुर में २ केस और मौत ०, दाहोद में २ केस और मौत २, वडोदरा में १ केस और मौत १, नर्मदा में २ केस और मौत ०, बनासकांठा में ४ केस और मौत ३, वडोदरा महानगर पालिका में २ केस और मौत १, भावनगर में १ केस और मौत ०, द्वारका में १ केस और मौत १, राजकोट महानगर पालिका में २ केस और मौत ०, कच्छ में १ केस और मौत ० मिलाकर कुल ८४ संदिग्ध मामले और ३३ मौत हुई हैं ।

प्राथमिक स्कूल के आचार्य ने विद्यार्थी से कार साफ करवाई, कांग्रेस की कड़ी कार्यवाही की मांग

राजकोट (ईएमएस) अभिभावक अपने बच्चों को स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने भेजते हैं ना कि मजदूरी करने सरकार भी बच्चों की पढ़ाई के लिए करोड़ों का अनुदान देती है, लेकिन कई स्कूलों में मासूम विद्यार्थियों से काम कराया जाता है ऐसी ही एक घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें विद्यार्थी कार साफ करते दिख रहे हैं यह घटना है राजकोट तहसील के मधरवाडा स्थित सरकारी प्राथमिक स्कूल की बताया जाता है कि विद्यार्थी जिस कार को साफ कर रहे हैं वह स्कूल के आचार्य की है

चौंका देनेवाला वीडियो सामने आने के बाद सवाल यह है कि क्या इस प्रकार बच्चे पढ़ाई करेंगे? बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने आते ना कि मजदूरी करने स्कूल की सफाई करने का काम भी विद्यार्थियों का नहीं होता स्कूल में साफ-सफाई इत्यादि के लिए भी सरकार की ओर से ग्रांट मिलती है इसके बावजूद विद्यार्थियों से स्कूलों में काम कराना दुर्भाग्यपूर्ण है सरकारी स्कूल का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने इस मामले में राजकोट डीपीईओ से पेशकर कड़ी कार्यवाही की मांग की है एक विद्यार्थी नेता ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों से मजदूरी कराए यह अपराध है, इसके बावजूद बच्चों का इस प्रकार शोषण और अत्याचार किया जाना शिक्षा क्षेत्र के लिए कलंक है राजकोट के मधरवाडा की सरकारी स्कूल के आचार्य ही विद्यार्थियों से अपनी कार साफ करवा रहे हैं इस मामले में उचित कार्यवाही की जानी चाहिए

बीजेपी से जुड़े विकास अहीर को सूरत पुलिस ने ड्रग्स बेचने के मामले में किया अरेस्ट

सूरत, २२ जुलाई । गुजरात की सूरत शहर पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले में हिंदूवादी नेता और बीजेपी कार्यकर्ता विकास अहीर समेत दो अन्य को एमडी ड्रग बेचने के मामले में अरेस्ट किया है । सोशल मीडिया पर मौजूद प्रोफाइल के अनुसार विकास अहीर हिंदू युवा वाहिनी गुजरात प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं । इसके साथ वह बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं । सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने प्रेस कांफ्रेंस करके शहर में एमडी ड्रग्स की बिक्री के मामले में पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी । गहलोत ने कहा कि सूरत में पहले ड्रग्स की खेप मुंबई से आती थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद इस धंधे में लिप्त लोगों ने मॉड्स ऑपरेंडी में बदलाव किया है । अब राजस्थान से जरिए सूरत में ड्रग्स की बिक्री कर रहे हैं । पुलिस ने विकास अहीर के विकास के साथ चेतन साहू और अनीश खान पठान को गिरफ्तार किया है । पुलिस के इनके पास से ३५४ ग्राम एमडी ड्रग्स मिला है ।

एक तरफ जहां ड्रग्स बेचने के मामले में सूरत पुलिस ने पुलिस ने विकास अहीर और उसके २ दोस्तों को अरेस्ट किया है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है । इटालिया ने लिखा है हिंदुत्व के नाम पर २०२२ के चुनाव में यही टोली उनके घर पर पहुंची थी ।सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने कहा है कि सामने आया है कि आरोपी आइसक्रीम पॉर्लर की आड़ में एमडी ड्रग्स का धंधा कर रहे थे । ये टू व्हीलर से डिलीवरी भी करते थे । गहलोत ने कहा पिछले कुछ समय में सूरत में ड्रग्स बेचने के ३७ मामले में दर्ज किए गए हैं । इनमें कुल ८५ आरोपियों को अरेस्ट किया है । गहलोत ने कहा एनडीपीएस एक्ट में अरेस्ट आरोपियों की संपत्ति की जांच भी जा रही है । अवैध और काली कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को सील किया जाएगा । सूरत पुलिस द्वारा ड्रग्स बेचने के मामले में अरेस्ट किए गए विकास अहीर ने सोशल मीडिया पर अपनी छवि एक हिंदू वादी नेता की बनाई है । एक्स पर अहीर ने अपने बॉयो में लिखा है कि पूर्व अध्यक्ष हिन्दू युवा वाहिनी गुजरात प्रदेश बताया है । इसके बाद अहीर ने खुद को बीजेपी युवा मोर्चा गुजरात से जुड़ा हुआ बताया है । अहीर ने बॉयो में खुद को आरएसएस को स्वयंसेवक भी बताया है । सूरत शहर पुलिस के अनुसार करीब एक महीने की होमवर्क और निगरानी के बाद तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है । पुलिस ने अनुसार पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी कुल मामले दर्ज हैं । पुलिस ने अनुसार ड्रग्स राजस्थान के जरिए सूरत में लाया जा रहा था ।

अहमदाबाद मण्डल ने 720 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त किया

पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मण्डल अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम संभव प्रयास कर रहा है और इसकी गति को बनाए रखा है। मण्डल रेल प्रबंधक श्री सुधीर कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में अहमदाबाद मण्डल ने जून 2024 में 720.52 करोड़ रुपये के कुल राजस्व के आँकड़े को पार किया। जो पिछले वर्ष जून 2023 के 677.11 की तुलना में 6.41% से अधिक है। बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के सक्रिय विपणन प्रयास एवं नीतियों में व्यापक बदलाव से यह उपलब्धि हासिल करने में सफलता मिली है।

उपलेटा का लाठ गांव 11 इंच बारिश से हुआ जलमग्न, जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है

राजकोट (ईएमएस) गुजरात में खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ सौराष्ट्र में लगातार बारिश में गांव गांव पानी में डूब गए हैं राजकोट जिले की उपलेटा तहसील के लाठ गांव में मानो आसमान फटा हो ऐसा नजारा सामने आया है लाठ गांव केवल 2 घंटों में 11 इंच बारिश में जलमग्न हो गया भारी बारिश के कारण लाठ गांव में वाहनों का आवागमन बंद हो गया है और सड़कों पर पानी भर जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है जानकारी के मुताबिक लोगों के घरों, दुकानों, स्कूलों समेत हर जगह बारिश का पानी घुस गया है जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है इतनी बारिश होने के बावजूद मेघा रुकने का नाम नहीं ले रहा है अभी भी बारिश हो रही है और इसका जोर बढ़ने का अनुमान है भारी बारिश के चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है और खेत भी पानी में डूब चुके हैं

देवभूमि द्वारका की कल्याणपुर तहसील में हुई भारी बारिश

कल्याणपुर, २२ जुलाई । देवभूमि द्वारका की कल्याणपुर तहसील में मानसून की जोरदार बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया । तहसील के कई गांवों में पानी भरने से आवाजाही बंद हो गई है । ग्रामीण क्षेत्रों के खेत तालाब और रास्ते नदी जैसी स्थिति में हो गए हैं । भारी बारिश के कारण कई लोगों के पानी में फंसने के बीच लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया । कल्याणपुर तहसील के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में ११ लोगों के पानी में फंसे होने की जानकारी पर प्रशासन ने सभी का रेस्क्यू किया है । केशवपुर गांव के ४ व्यक्ति, टंकारिया गांव के ४ व्यक्ति को प्रशासन ने पानी से बचाव किया । पानेली गांव के ३ व्यक्ति को हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया । पानी भरने की जानकारी होने पर इस क्षेत्र के तहसीलदार और उप तहसीलदार घुटने तक पानी में जाकर लोगों के बचाव में जुटे रहे । द्वारका के कल्याणपुर गांव में मूसलाधार बारिश के कारण गांव में नदी बहने जैसे हालात हो गए हैं । कल्याणपुर में ८ इंच बारिश हुई है । भारी बारिश के कारण गांव के बाजार, सड़क और खेतों में पानी भर गया है । घुटने तक पानी में जाकर लोग जरूरी कामकाज कर रहे हैं । सबसे अधिक हालत खराब पशुओं और मवेशियों को देखी गई । लोग-बाग अपने मवेशियों को बचाने में प्रयासरत देखे गए । भारी बारिश के कारण एक दर्जन से अधिक गांवों का सम्पर्क भी टूट गया है । सौराष्ट्र में सोमवार को मूसलाधार बारिश हो रही है । द्वारका में भारी बारिश के कारण जन-जीवन ठप पड़ गया है । दक्षिण गुजरात में भी भारी बारिश का दौर जारी है । राज्य में सुबह ६ बजे से शाम ४ बजे तक राज्य की कुल २५० तहसीलों में से १३९ तहसील में बारिश हुई है ।

देवभूमि द्वारिका की कल्याणपुर तहसील में ११ इंच, जूनागढ़ की माणावदर में ६.५४ इंच, सूरत की पलसाणा में ६ इंच, बारडोली में ५.५९ इंच, कामरेज में ४.६९ इंच, मांडवी में ३.९० इंच, जूनागढ़ की मालिया हाटिया में ५.३१ इंच, द्वारका में ५.३१ इंच, राजकोट की उपलेटा में ५ इंच, गिर सोमनाथ की गिर गढ़डा में ४.७२ इंच, वलसाड की वापी में ३.५० इंच, पोरबंदर की कुतियाणा में ३.४३ इंच, वलसाड की कपराडा में ३.३१ इंच, पोरबंदर के राणावाव में ३.२७ इंच बारिश हुई है ।

संकरा आई अस्पताल में एक वर्षीय शिशु की कॉर्नियल अल्सर की सफल सर्जरी की गई

2024: एक हालिया केस अध्ययन में आंख की चोट के लक्षणों का अनुभव करने वाले छोटे बच्चों में संपूर्ण आंखों की जांच के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस मामले में एक साल की बच्ची, शीला (बदला हुआ नाम) शामिल थी, जिसकी दाहिनी आंख में कॉर्नियल अल्सर था, जो संभावित रूप से दृष्टि के लिए खतरा था।

इस मुद्दे पर बोलते हुए डॉ. निशा आहूजा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सलाहकार, कॉर्निया, मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जरी, संकरा आई हॉस्पिटल, आनंद ने कहा, ''कॉर्निया अल्सर एक गंभीर चिंता का विषय है, जो विशेष रूप से छोटे बच्चों में कॉर्निया अंधापन के महत्वपूर्ण प्रतिशत में योगदान देता है छिपे हुए विदेशी निकायों की संभावना को नजरअंदाज न करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, यहां तक कि उन स्थितियों में भी जहां कारण अस्पष्ट लगता है, और विदेशी निकायों के सफल उपचार को सुनिश्चित करने के लिए, यह उनकी परीक्षाओं में सावधान रहने के लिए एक आदर्श अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, खासकर जब बच्चों के साथ व्यवहार करते समय मौखिक रूप से अपनी परेशानी के बारे में नहीं बता सकते। छोटे बच्चों में नेत्र आघात के सभी मामलों में पलक पुनरीक्षण सहित एक व्यापक नेत्र परीक्षण मानक है। शीघ्र निदान और उचित प्रबंधन को प्राथमिकता देकर, हम बच्चे की दृष्टि बचाने की संभावनाओं में काफी सुधार कर सकते हैं।ठ

एआईआरएफ और एनएफआईआर का संयुक्त वक्तव्य

हाल ही में भारतीय रेलवे पर कुछ संगठनों द्वारा एक बयान जारी किया गया है, जिससे रेलवे के बारे में भ्रम और अविश्वास की गुंजाइश पैदा हो गई है।

2. सभी रेलवे कर्मचारी ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए अपनी पूरी क्षमता से दिन-रात मेहनत करते हैं। यह बात साल दर साल रेल दुर्घटनाओं में कमी से स्पष्ट होती है।

इसके अलावा, भले ही दुर्घटना का प्रथम दृष्टया कारण बता दिया गया हो, लेकिन रेलवे में होने वाली हर दुर्घटना के बाद हमेशा सीआरएस या बहु-विषयक टीम द्वारा दुर्घटना के कारण का पता लगाने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए विस्तृत जांच की जाती है। इस विस्तृत जांच के आधार पर कार्रवाई की जाती है। दोनों महासंघ (एआईआरएफ और एनएफआईआर) सुरक्षा मानकों को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी देते रहे हैं।

यह कुशल और मेहनती रेलवे कर्मचारी ही हैं जो इस देश के लोगों के लिए परिवहन का सबसे किफायती साधन उपलब्ध कराते हैं। हम फेडरेशन गर्व से कहते हैं कि हम यात्रियों की सुरक्षा और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए काम करना जारी रखते हैं हालांकि यह दुखद है कि रेलवे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करने के बजाय, रेलवे कर्मचारियों का मनोबल गिराने वाली टिप्पणियां की जा रही हैं।

3. बेशक, काम की कठोरता को कम करने के लिए कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। हम चीजों को और बेहतर बनाने के लिए सभी स्तरों पर नियमित बैठकें और बातचीत कर रहे हैं।

4. हाल के वर्षों में 5 लाख से अधिक कर्मचारी रेलवे में शामिल हुए हैं। हमने पाया है कि हाल ही में 1.5 लाख उम्मीदवारों को नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 18,000 से अधिक लोको पायलटों की भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वार्षिक परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया गया है और जूनियर इंजीनियर, तकनीशियन आदि जैसी श्रेणियों में भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

भारतीय रेलवे में प्रशिक्षण की एक सुस्थापित प्रणाली है। सभी रेलवे कर्मचारी भारतीय रेलवे के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में रिफ्रेशर कोर्स, सुरक्षा पाठ्यक्रम, उपकरण पाठ्यक्रम आदि के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण लेते हैं। जब भी नई तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो लोको पायलटों को प्रशिक्षण/परामर्श के बाद योग्यता प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।

5. महासंघ अपने अधिकारियों के साथ कर्मचारियों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तथा ऐसे समाधान निकाले जा रहे हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हों।

6. रेलवे 12 लाख कर्मचारियों वाला एक विशाल संगठन है। इस संगठन की कार्यप्रणाली बाहरी लोगों के लिए आसानी से समझ में नहीं आती। ऐसे जटिल कार्य परिदृश्य में, कामकाज को समझे बिना, जाने-अनजाने में की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ राष्ट्र के समग्र हित में नहीं हो सकती हैं। इसलिए फेडरेशन व्यक्तियों और संगठनों से राष्ट्र के समग्र हित के लिए रचनात्मक तरीके से सहायता करने की अपील करता है।

7. हम गैर-रेलवे यूनियनों/संगठनों आदि द्वारा जारी किए गए बयानों की सराहना नहीं करते हैं, क्योंकि इन बयानों से आम लोगों के मन में आशंका और भय का माहौल